हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

8 मार्च, 1989

खंण्ड 1, अंक 10

अधिकृत विवरण

बुधवार, 8 मार्च, 1989

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर	(10)28
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(10)31
बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट	(10)32
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(10)35
वर्ष 1989– 90 का बजट पेश करना	(10)36

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 8 मार्च 1989

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, 'विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ मैं प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोन्दिर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्ष ता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होगें।

School Buildings Collapsed due to Rains/Floods

***671. Shri Rattan Lal Kataria :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether any school buildings have collapsed due to recent heavy floods in the State; and

(b) if so, the details thereof togetherwith the steps taken to reconstruct the said buildings ?

खाद्य तथा पूर्ति मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज):

(क) जी नहीं। कुछ विद्यालय भवन आशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा उनकी सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

बाढ से आशिक रूप में क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की सूची

जिला अम्बाला

क्रमांक	विद्यालय का नाम	क्षतिग्रस्त भवन का विवरण
1	रा० उ० वि० नन्यौला	4 कमरे क्षतिग्रस्त
2.	रा० उ० वि० बकनौर	चार दीवारी गिर गई, छतों की मुरम्मत की आवश्यकता है
3	रा० उ० वि० ईस्माईलपुर	दो कमरों की मुरम्मत की आवश्यकता है
4.	रा० उ० वि० नगल	बरामदा तथा चार दीवारी क्षतिग्रस्त
5.	रा० उ० वि० खैरा	चार दीवारी गिर गई
6	रा० उ० वि० जनसुई	5 कमरों की छतें, दीवारें तथा फर्श क्षतिग्रस्त
7.	रा० मा० वि० छप्परा	सभी कमरों की छतें क्षतिग्रस्त
8.	रा० प्रा० पा० कुर्बानपुर	सभी कमरों की छतें क्षतिग्रस्त
9.	रा० प्रा० पा० मुजाकरा	सभी कमरों की छतें क्षतिग्रस्त
10.	रा० प्रा० पा० गौरसिया	चार कमरों की छतें/चार दीवारी क्षतिग्रस्त

	जिला सिरसा	
11.	रा० उ० वि० चामल	चार दीवारी, बरामदा, शौचालय क्षतिग्रस्त
12.	रा० उ० वि० नेजा डेला खुर्द	चार दीवारी, दो कमरे, शौचालय व बरामदा क्षतिग्रस्त
13	रा० उ० वि० जोधका	साईंस कक्ष, सीढ़ियां तथा चार कमरों की छतें क्षतिग्रस्त
14.	रा० उ० वि० निहारी	दो कमरों की छतें क्षतिग्रस्त
15.	रा० उ० वि० बहावदीन	एक कमरे की छत, चार दीवारी, साईकल स्टैण्ड की चार दीवारी क्षतिग्रस्त
16.	रा० उ० वि० दडबी	चार दीवारी क्षतिग्रस्त
17	रा० क० उ० वि० रानियां	चार दीवारी तथा शौचालय क्षतिग्रस्त
18.	रा० उ० वि० एलनाबाद	दो कमरे क्षतिग्रस्त
19.	रा० उ० वि० नेजा डेला कलां	चार दीवारी तथा 2 कमरों में दरार
20.	रा० मा० वि० फरवाई कलां	चार दीवारी व छः कमरे तथा गेट

		क्षतिग्रस्त
21.	रा० प्रा० पा० सहरानी	चार दीवारी, 2 कमरे व फर्श क्षतिग्रस्त
22	रा० प्रा० पा० फरवाई खुर्द	6 कमरे, बरामदा, चार दीवारी तथ शौचालय क्षतिग्रस्त
23	रा० प्रा० पा० रसूलपुर	पूरा भवन क्षतिग्रस्त
24	रा० प्रा० पा० रानियां	चार दीवारी, बरामदा व 2 कमरे क्षतिग्रस्त
	जिला हिसार	
25.	रा० मा० वि० करनौली	आशिक रूप से क्षतिग्रस्त
26.	रा० उ० वि0 हिजरावार खुर्द	आशिक रूप से क्षतिग्रस्त
27.	रा० प्रा० पा० बहल भूमियां	आशिक रूप से क्षतिग्रस्त
	जिला सोनीपत	
28.	रा० मा० वि० जसराना	सारा भवन क्षतिग्रस्त
29.	रा० मा० वि० छपरा	चार दीवारी का कुछ भाग क्षतिग्रस्त
30.	रा० मा० वि० बली ब्रहमणान	चार दीवारी का कुछ भाग क्षतिग्रस्त

31.	रा० मा० वि० पुट्ठी	सभी कमरों की छतें व फर्श क्षतिग्रस्त
32.	रा० मा० वि० कासण्डी	चार दीवारी क्षतिग्रस्त
33.	रा० प्रा० पा० असदपुर	भवन का पूरा भाग क्षतिग्रस्त
34.	रा० प्रा० पा० मनौंली ट्राकी ब्रांच	भवन का पूरा भाग क्षतिग्रस्त
35.	रा० प्रा० पा० सिवाना	दो कमरों की छत क्षतिग्रस्त
36.	रा० प्रा० पा० बिलबिलान	चार दीवारी का कुछ भाषा क्षतिग्रस्त
37.	रा० प्रा० पा० काहनी	चार दीवारी का कुछ भाग क्षतिग्रस्त
38	रा० प्रा० पा० रभड़ा	कमरे की छत खराब तथा चार दीवारी में दरार
39.	रा० प्रा० पाए सोइटी	दो कमरे क्षतिग्रस्त
	जिला करुक्षेत्र	छः कमरे असुरक्षित हो गये
40	रा० मा० वि० शरीफगढ	दो कमरों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और छते क्षतिग्रस्त
41.	रा० मा० वि० भुन्नी	सभी दीवारों में दरारें पड़ गई हैं

42.	रा० प्रा० पा० हलदाहैंड़ी	सभी कमरों की दीवारों में दरारें तथा छतें क्षतिग्रस्त
43.	रा० प्रा० पा० मोहड़ी	चार दीवारी गिर गई
44.	रा० उ० वि० दीवाल	चार दीवारी गिर गई
45.	रा० उ० वि० साकरा	

श्री रत्न लाल कटारियाः स्पीकर सर, कुरक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के डैमेजड स्कूलो की जो लिस्ट दी हैं, उस में कई स्कूलों के नाम नही हैं। मेरे चुनाव क्षेव के गुमथलाराव, गल– जाना जैसे स्कूल बिल्कुल तहस–नहस हो गये हैं और इनके अलावा, कम से कम 20 स्कूल और डैमेज हुए हैं। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या यह लिस्ट सर्वे करने के बाद तैयार की गई है।

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष जी, सर्वे के बाद ही मैंने सूची पटल पर प्रस्तुत की है। अगर सव नहीं होता तो सूची पटल पर कैसे प्रस्तुत की जाती?

श्री भागमलः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इन्होंने अम्बाला की जो लिस्ट दी है, उस में गवर्नमैंट मिडिल स्कूल मछरौली का नाम क्या नहीं आया उसके दो कमरों की क्त बरसात के कारण बैठ गई हैं, इसकी जानकारी कैसे रह गई?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने खुद कहा कि, बरसात में छत बैठ गई लेकिन सवाल फ्लड का है। फ्लड में रजो स्कूल कुलैप्स हुए, उनकी सूची मांगी गई थी। तो फ्लड में जो स्कूल पारशियली डैमेज हुए हैं, उनकी सूची दे दी गई है। इसके अलावा, भारी वर्षा से 260 स्कूल डैमेज हुए हैं। अलग–अलग जगहों पर जो स्कूल डैमेज हुए हैं, उनकी सूची नहीं मांगी गई थी, इसलिये उनका नाम इसमें नही हैं।

श्री रत्न लाल कटारियाः स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदया मेरे साथ मेरे हल्के में चलकर स्कूल की बिल्डिंग की कंडीशन को देखने के लिये तैयार हैं? क्या समय निकाल कर मेरे साथ चल कर उन स्कूलों का मूआईना करेंगी? बहन जी, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवैसिज कमेटी की चेयरमैन हैं। जो स्कूल डैमेज हुए हैं उनके बारे में इन्होंने मीटिंग में कहा था कि आपकी तसल्ली कर दी जायेगी।

श्रीमती सुषमा स्वराजः अगर सदस्य की तसल्ली मेरे द्वारा स्कूल का मुआईना करने से होती है तो मैं जरूर इनके साथ समय तय करके स्कूलों का मुआईना करूंगी।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, जो बिल्डिंग खराब हुई है, चाहें बरसात से खराब हुई है या फ्लड से, एक ही बात है, क्योंकि बाढ़ भी बरसात के कारण ही आती है। क्या मंत्री जी बताएंगी कि अलग–अलग जिलों में इस प्रकार के कितने भवन

क्षतिग्रस्त हुए हैं बार उनके निर्माण के लिये या ठीक करने के लिये कितने पैसों का प्रावधान किया गया णै और कब तक उनकी मुरम्मत करवा दी जाएगी?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष जी, शायद माननीय सदस्य को कुछ याद हो, मैंने कुछ दिन पहले सदन को यह अवगत करवाया था कि हमने स्कूलों की मुरम्मत करने की पूरी पद्धति बदल दी है। आज से पहले इस तरह के गिरे हुए स्कूल या जिनकी मुरम्मत की जानी थी, उनकी मुरम्मत करवाने की प्रक्रिया बहुत पेचीदा थी। पहले पी० डब्लयू० डी० को कहते थे कि जाकर उसका मुआईना करें। पी० डब्लयू० डी० पहले उसको अपनो बुक्स पर लेता था, फिर ऐस्टीमेट तैयार करता था। ऐस्टीमेंट तैयार करने के बाद उनकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल ली जाती थी औंर उसके बाद काम शुरू होता था। मैंने सदन को अवगत करवाया था कि किस प्रकार हमने नीति परिवर्तन किया है। बिल्डिंग फण्ड का 70 प्रतिशत पैसा जो पहले डायरैक्टोरेट को जाता था, अब हमने तय किया है कि वह पैसा उसी स्कूल में रहैंगा और उसी स्कूल का हैडमास्टर मुरम्मत करवा सकेगा। जहां–जहां छोटे–छोटे काम करने हैं हमने उसमें पैसे की मिकदार ज्यादा की है। हमने कहा है कि 5000 रुपये तक प्राईमरी स्कूल का हैड टीचर, 8000 रुपये तक मिडल स्कूल का हैडमास्टर और 15000 रुपये तक सीनियर स्कूल हैड टीचर खर्च कर सकता है। तो इस नई नीति के तहत

हैडमास्टर और हैड टीचर अपने आप ही स्कूल की मुरम्मत करवा लेंगे और काम ज्यादा आसान हो जायेगा।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐनुअल रिपेयर के लिये जो बिल्डिंग्ज हैं, क्या उनका पैसा अलग से रखा जाता है? क्या यह सुनिश्चित कर लिया है कि उनकी रिपेयर हर साल होती रहैंगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज: जी हां, उनकी रिपेयर हर साल होती रहैंगी। वह पैसा पहले प्लान बजट का हिस्सा नहीं होता था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में यह योजनागत बजट का हिस्सा हो गया और जो योजनागत बजट का हिस्सा होता है उसका बाकायदा यूटीलाईजेशन सर्टीफिकेट देना पड़ता है और उसका बार–बार रिव्यू होता है। योजनागत बजट का हिस्सा होने के बाद चूंकि उस पर निगरानी रखी जाती है, इसलिये साथ के साथ रिपेयर हो जाती है।

श्री भागमल: स्पीकर साहब, बहुत से स्कूलों में बिल्डिंगें नहीं हैं। क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि बिल्डिंग फण्ड के इलावा जो दूसरे फण्ड है, उनको कन्वर्ट करके बिल्डिंग बनाने पर खर्च करने का कोई प्रावधान जेरेगौर है ?

श्रीमती सुषमा स्वराज: दूसरे फण्डज को कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नही है। अगर उनको कन्वर्ट कर भी दिया जाता है तो भी वे फण्ड इतने कम होते हैं कि उनसे रीकन्स्ट्रक्शन हो

ही नहीं सकती। हमारे यहां कन्स्ट्रक्शन का हैड अलग है और वह भी योजनागत बजट का हिस्सा है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता दूं कि हमें 4 करोड़ 88 लाख रुपये अलग से कन्स्ट्रक्शन के लिये मिल रहैं है जिससे हम बिल्डिंगें बनायेंगे। इसके इलावा, एन०आर०इ०पी० और आर०एल०इ०जी०पी० का जो पैसा आता है, वह भी नये कमरे बनाने पर खर्च होता है। इस तरह कन्स्ट्रक्शन के लिये हमारे पास अलग हैड है जिससे हम नई इमारतें बनवायेंगें।। दूसरे फण्डज कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि अब जो नई नीति इन्होंने तय की है, उसके मुताबिक किसी स्कूल की बिल्डिंग चाड वह प्राइमरी स्कूल है, चाहैं मिडिल स्कूल है, चाहैं हाई स्कूल है, जिसको पी०डब्लयू०डी० ने टेक ओवर नहीं किया था, उस स्कूल के हैड क्या उस पैसे का खर्च कर सकेगे?

श्रीमती सुषमा स्वराजः मैं इसको बिल्कुल कलियर कर देती हूं कि इस नीति के तहत वर्क पी० डब्लयू० डी० की बुक्स पर ले जाने की जरूरत नही है। जो वर्क पी० डब्ल्यू० डी० ब्रुक्स पर नही है उस पर भी हम आसानी से खर्च कर सकते हैं।

सेठ लछमन दास बजाजः अध्यक्ष महोदय, बरसात के दिनों मे गवर्नमैंट कालेज करनाल के दो कमरों की छतें बिल्कुल

गिर चुकी हैं। इसके अलावा गवर्नमैंट हाई स्कूल की आधी बिल्डिंग नकारा हो गई है। क्या वह बन जाएगी?

श्रीमती सुषमा स्वराजः बिल्कुल बन जाएगी।

ई० जगपाल सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने बताया है कि कुछ फण्ड रिपेयर के लिये हैडमास्टर को दिये जायेगे 1 क्या मन्त्री महोदया बतायेंगी कि 1988–89 में कितना पैसा दिया गया है और नैक्सट ईयर में कितना दिया जायेगा?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष जी, मैंने यह बिछल नहीं कहा कि हम पैसा उनको देंगे। मैंनै यह कहा है कि उनके स्कूल से जो पैसा बिल्डिंग फण्ड का इकट्ठा होता है, उसका 70 प्रतिशत वहीं रह जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 693

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी किशन सिंह सांगवान, इस समये सदन में उपस्थित नहीं थे।

Upgradation of Schools

***820. Shri Ranjit Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state the total number of Government schools for boys upgraded from Primary to Middle and from Middle to High Schools in the State during the year 1988-89

(upto 31st January, 1989) districtwise, separately ?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): वर्ष 1988–89 में 31– 1–89 तक कोई स्कूल स्तरोन्नत नहीं किया गया है।

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूगा कि ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से पूरे साल में कोई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ? अगर अपग्रेड हुए हैं तो लड़कियों के और को ऐजूकेशन के कितने स्कूल थे जो अपग्रेड हुये ?

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में 500 स्कूलों को प्राईमरी से मिडल करने का लक्ष्य रखा गया था। 100 स्कूल मिडल से हाई करने का लक्ष्य था लेकिन वर्ष 1986–87 चूंकि चुनाव का साल था, इसलिये जाने वाली सरकार पहले ही लक्ष्य को पूरा कर गई। अगले वर्ष जब बजट परपोजल प्लेनिंग कमीशन के सामने गया तो प्लेनिंग कमीशन का जो वर्किंग ग्रुप था, उसने हमारा सुझाव यह कह कर ठुकरा दिया कि चूंकि साधनों का अभाव है और आपने अपना लक्ष्य पहले ही पूरा कर लिया है इसलिये बजट का प्रावधान नहीं हो सकता। अतः कोई स्कूल अपग्रेड करने का निर्णय नहीं लिया गया। इसके बाद, जब दोबारा प्लेनिंग बोर्ड की मीटिंग हुई तो हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि भले ही उन्होंने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है, लेकिन मैं कन्याओं की शिक्षा के लिये बहुत चिंतित हूं, इसलिये

अलग से हम कुछ प्रावधान करेंगे। तुम इस समय लड़कियों के 50 स्कूल प्राईमरी से मिडल और 25 स्कूल मिडल से हाई कर दो। प्लेनिंग बोर्ड की यह मीटिंग मई में हुई और उसमें इस बात का प्रावधान किया गया। इसके बाद बजट में व्यवस्था करने के लिये केस एफ०डी० में भेजा गया। अब उसका बजट परपोजल हमारे पास बनकर आया है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि 31– 1– 1989 तक कोई स्कूल अपग्रेड किया गया है या नहीं। मैंनै इसके जवाब में कहा एं कि 31– 1– 1989 तक कोई स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया, लेकिन इस वर्ष में 18 फरवरी, 1989 को 50 कन्या स्कूल प्राईमरी से मिडल और 25 कन्या स्कूल मिडल से हाई करने का निर्णय लिया गया है।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने बताया कि इस वर्ष स्कूल अपग्रेड करेंगे। क्या स्कूल अपग्रेड करते समय सिरसा जिले को, जहां इस समय सबसे कम स्कूल हैं, ज्यादा स्कूल खोलने के लिये प्रैफरेन्स देंगे?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष जी, जब हम इस तरह की अपग्रेडेशन करते हैं तो यह ध्यान रखते हैं कि असंतुलन खत्म हो। अब मैं भाई भागीराम जी की सूचना के लिये बता दूं कि इस बार भी जो 50 स्कूल प्राईमरी से मिडल हुए हैं, उसमें सिरसा जिला के असंतुलन को देखते हुये 7 स्कूल अपग्रेड कर दिये हैं और अगले वर्ष भी इस असंतुलन को कम करने के लिये सिरसा जिले को जरूर प्राथमिकता देंगे।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने अपने जवाब में बताया है कि 50 प्राईमरी स्कूलों को अपग्रेड करके मिडल स्कूल बनाना है और 25 मिडल स्कूलों को हाई स्कूल बनाना है। गलती से कहो, या संयोगवश कहो, मेरे गांव में पहले ही कन्याओं का मिडल स्कूल है लेकिन यह स्कूल प्राईमरी स्कूल से मिडल स्कूल अपग्रेड करने की लिस्ट में शामिल था। क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि उसको मिडल स्कूल काऊंट करके हाई स्कूल अपग्रेड कर दिया गया है या वह प्राईमरी की लिस्ट में ही हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराजः यह स्कूल मिडल था लेकिन गलती से प्राईमरी से मिडल बनाये जाने वाली सूची में शामिल हो गया था। माननीय सदस्य ने पहले भी इसके बारे में जानकारी दी थी और मैंने तभी इन्हें आश्वासन दे दिया था कि इसको हम मिडल से हाई स्कूल बनाए जाने वाली लिस्ट में शामिल कर लैंग।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, कुछ गांवों में प्राईमरी स्कूल अभी भी टैम्पोरेरी हैं और उन्हैं ब्रांच स्कूल के नाम से जाना जाता है लेकिन वहां मिडल या हाई स्कूल की जरूरत है क्योंकि लड़कियों को पढ्ने के लिये बाहर जाना मुश्किल है। क्या इन्होंने ऐसा सर्वे करवाया है ताकि पिक एण्ड चूज की पालिसी को तिलांजलि देकर मैरिट के आधार पर अपग्रेड करने का कोई प्रोग्राम लागू किया जा सके?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि हमारी सरकार पिक एण्ड चूज की पालिसी पर चल ही नहीं रही है। इसको पहले तिलांजलि देकर ही हम सरकार में आए थे। जहां तक सर्वे का सवाल हए, मैं सारे माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह बता दूं कि अगले साल हमारा लक्ष्य लगभग 100 प्राईमरी से मिडल, 50 मिडल से हाई और 25 हाई से सीनियर सैकेण्डरी स्कूल अपग्रेड करने का है। मैं सारे सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहती हूं कि मुख्य मंत्री महोदय ने अपग्रेडेशन के लिये स्कूल छांटने के लिये एक कमेटी का गठन किया है, उसमें उप मुख्य मंत्री हैं, मैं हूं, बाबू मूल चन्द जैन हैं और चौयरमैन ऐजूकेशन बोर्ड हैं। सारे एम०एल०ए० साहिबान से मैं यह कहना चाहूंगी कि वे अपने हल्के का सर्वे करके जिन–जिन स्कूलों को वे समझते है कि वे आधार पूरा करते ऋ हैं और यह–अपटेड होने चाहिए, उन सबके प्रस्ताव मेरे पास 15 अप्रैल तक भिजक दें। वे अपने आप ही सर्वे कर लें और अपनी मांग हमारे पास भेज दें। उसके बाद कमेटी फैसला। करेगी। केवल इलाके की मांग को और अपग्रेडेशन के आधारों को पूरा करने वाली, बात को क्राईटेरिया रखा जाएगा। इसमें कोई पिक एण्ड चूज और फेवरेटिज्म नहीं होगी।

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने अभी कहा है कि स्कूल अपग्रेडेशन के लिये मैम्बर साहैंबान नाम भेज दें। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि उसका

क्राईटेरिया क्या होगा? दूरी होगी या बच्चों की स्ट्रैन्थ होगी? इसके अलावा, क्या 10 + 2 के स्कूल बनाने का भी कोई विचार है?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि हमने 100 प्रईमरी से मिडल, 50 मिडल से हाई और 25 सीनियर सैकेन्डरी स्कूल जिसको 10 + 2 कहते हैं, अपग्रेड करने हैं। जहां तक आधार का सवाल है, प्राईमरी से जो मिडल किए जाने हैं, उनमें कम से कम 8 कमरे टीचिंग के लिये होने चाहिएं और 150 बच्चे होने चाहिए और जो पहले स्कूल हैं उससे कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। इसीतरह जो मिडल से हाई हैं उसमें कम से कम 10 कमरे टीचिंग केलिये होने चाहिए। जो सीनियर सैकेन्डरी करने हैं, उनके लिये यह ध्यान रखें कि इनफ्रास्ट्रक्टचर फैसीलिटी पूरी होनी चाहिए, जैसे फरनीचर, स्पोर्टस का सामान आदि क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता हैं। जो स्कूल इन आधारों को पूरा करते हों, इलाके की मांग को देखते हुए हम उनका निरीक्षण करवाएंगे।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या अब तक उन्होंने इस बारे में कोई जांच पड़ताल की है और जांच पडताल के अनुसार कितने स्कूल भवन की शर्तें पूरी करते हैं और वे किस किस हल्के में हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, इस तरह का कोई सर्वे नहीं होता। अपग्रेडेशन की जो मांगें आती हैं, केवल उन्हीं का निरीक्षण करवाया जाता है। पिछले वर्ष जितनी मांगें आई थीं उनका निरीक्षण खुरवा कर जो स्कूल आधार पूरा करते थे, वे अपग्रेड हो गए। इस तरह का कोई सर्वे अभी तक नहीं हुआ है जिससे दूह पता चले कि कितने स्कूल इन आधारों को पूरा करते हैं।

श्री उदय भानः स्पीकर साहब, मेरा क्षेत्र हसनपुर है जोकि पूरा रूरल एरिया है। उसमें एक भी 10 + 2 स्कूल लड़कों के लिये नहीं है। क्या उस क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी? साथ ही मंत्री महोदया यह भी बता दें कि जो स्कूल अपग्रेड हो रहैं बै, उनमें से फरीदाबाद जिले में कितने अपग्रेड हो रहैं हैं और क्या उनमें मेरे क्षेत्र का भी कोई स्कूल हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही क्राईटेरिया की बाबत बता दिया है। माननीय सदस्य कह रहैं हैं कि इनकी कान्स्टीचुऐन्सी में तुक भी सीनियर सैकेन्डरी स्कूल नही है। यह तो अपने आप में क्राईटेरिया है। मैंने शुरू में कहा है कि हम असन्तुलन को समाप्त करेंगे और यह सब से बड़ा असन्तुलन है कि 90 हल्कों में से एक हल्का ऐसा है जहां एक भी 10 + 2 स्कूल नहीं है। अगर यह फैक्ट हुआ तो इनके यहां जरूर स्कूल अपग्रेड कर दिया जाएगा। जहां तक फरीदाबाद जिले का सवाल है, उस जिले में अभी हमने केवल एक स्कूल' लिया है वह स्कूल

है शहीद राजेन्द्र सिंह कन्या प्राईमरी विद्यालय, हथीन जोकि भाई भगवान सहाय रावत के हल्का में पड़ता है। हसनपुर का इसमें कोई नही है।

Improvement of Parks in Faridabad Complex Administration

***859. Shri Kundan Lal Bhatia :** Will the Minister of State for Local Government be pleased to state-

(a) whether it is a fact that parks, in Faridabad Complex Administration, are in poor condition; and

(b) if so, the steps so far taken to improve the condition of these parks as referred to in part (a) above ?

स्थानीय शासन राज्य मन्त्री (श्री ए०एस० भडाना):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कुन्दन लाल भाटिया: स्पीकर साहब, फरीदाबाद जिले में 90 प्रतिशत पार्कों की हालत बिल्कुल बुरी है। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि यह कब तक ठीक कर दी जाएगी।

श्री ए० एस० भडाना: स्पीकर साहब, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पार्क बिल्कुल ठीक हैं। उनको ठीक करने की बात तो तब सोची जाएगी, जब वे खराब हो।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, हमारे आदरणीय मन्त्री महोदय ने कहा कि सभी पार्क बहुत अच्छे हैं और उनको ठीक करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन क्या सरकार के नोटिस में यह बात आई है कि पब्लिक पार्कों को कुछ लोगों को पहली सरकार ने अलौट कर दिया था?

श्री ए० एसः भडानाः इसके लिये यदि डा० साहब सेपरेट नोटिस दें तो मैं इन्हैं जरूर जवाब दूंगा।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): ग्रीन बैलट को फरीदाबाद में तो नहीं लेकिन गुड़गांव में पिछली सरकार ने अलौट किया था।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आदरणीय संसदीय कार्य मन्त्री महोदय श्री भडाना साहब की मदद पर आए यह इन्होंने बड़ा अच्छा किया। वैसे तो श्री भडाना साहब भी बड़े होशियार हैं लेकिन पता नहीं उनके गुणों का इस्तेमाल क्यों नही होने जा रहा। खैर, मैं आपके द्वारा इनसे एक बात जानना चाहूंगा। संसदीय कार्य मन्त्री जी ने फरमाया है कि गुडगावा में ग्रीन बैल्ट को अलाट किया गया था। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि उस अलौटमैंट को, इस सरकार ने आने के बाद कैंसिल किया है या नहीं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः इस समय तक तो नहीं किया हैं।

राजस्व मन्त्री (श्री सूरज भान): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न दरअसल मेरे डिपार्टमैट से सम्बन्धित है। इसलिये मैं बताना चाहता

हूं कि फरीदाबाद में भी एक पब्लिक पार्क की जमीन पिछली गवर्नमैंट ने जाने से 4 दिन पहले एक धर्मशाला बनाने के नाम पर एक आदमी को दे दी थी। हमने उस अलौटमैंट को कैन्सिल करने की कोशिश की थी लेकिन चूकि पेमैन्ट हो चुकी थी और कब्जा दिया जा चुका था, इसलिये उसे वापिस लेना मुश्किल हो गया।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि सारे शहरों में जो पार्क हैं, उन पर हर साल सरकार कितना खर्चा कर रही हैं?

श्री ए० एस० भडाना: इसके लिये. माननीय सदस्य सैपरेट नोटिस दें।

श्री कुन्दन लाल भाटिया: स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने बताया है कि फरीदाबाद के सारे पार्क ठीक हैं। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी फरीदाबाद के पार्कों के दर्शन भी किए हैं? फरीदाबाद में अभी कई पार्कों की चारदीवारी नही बनी है। कई पार्कों में कच्चो के बैठने के लिये कोई चीज नही हैं। कोई लाईट का प्रबन्ध ' नहीं हैं और मन्त्री जी ने कह दियार कि सभी पार्क ठीक हैं। इसलिये मैं मन्त्री जो से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने वे पार्क कभी देखे हैं?

श्री ए० एस० भडाना: स्पीकर सर, 'माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि 1988– 89 में पार्कों के०पर हम 20 लाख रुपये लगा चुके हैं और कई जगह उन पर काम शुरू है। श्री

भाटिया साहब मेरे पास के ही रहने वाले है। मेरा घर उनके घर से कोई दूर नही है। यदि यह कोई पार्क मुझे बता देंगे तो उसको ठीक करवा देंगे।

श्री कुन्दन लाल भाटिया: मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वे किस दिन मेरे साथ पार्क देखने के लिये जायेगे?

श्री ए० एस० भडाना: अगर अभी भी श्री भाटिया साहब चाहैं तो मैं इनके साथ इसी समय चलने के लिये तैयार हूं। वैसे मैं स्पीकर साहब, बताना चाहूंगा कि आगे के लिये भी फरीदाबाद में प्रशासन ने पार्कों को ठीक करने के लिये 1० लाख रुपए का प्रावधान रखा है।

श्री बलवीर सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से जलना चाहूंगा कि क्या फरीदाबाद के इलावा उन्होंने बाकी हरियाणा की कितनी ऐसी म्पूनिसिपल कमेइटियों का विजिट किया है और पार्कों की हालत देखी है? अगर देखी है तो कहा–कहीं देखी है? जिन कमेटियों में भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं, क्या उनका दौरा करके उनके खिलाफ कोई नोटिस लेंगे और कार्यवाही करेंगे?

श्री ए० एस० भडाना: स्पीकर साहब, मैं सारी म्यूनिसिपल कमेटियों का दौरा कर चुका हूं और जहां हमने कमी

देखी है, उनके लिये पैसा भेजा है। अगर कोई कमी हैं तो सदस्य साहैंबान नोटिस दे दे, जवाब दे देंगे।

श्री रघु यादवः क्या माननीय मन्त्री फरीदाबाद के पार्कों का दौरा करने के लिए केवल कुछ दिन के लिये जा रहैं हैं या परमानेंट जा रहैं हैं। (हंसी)

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः मंत्री जी ने अभी–अभी जवाब दिया कि कोई भी पाके खराब नहीं है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो 10 लाख रुपये इन्होंने एनाऊंस किए हैं अगले साल के लिये, उसे कहां कहां खर्च करेंगे?

श्री ए० एस० भडानाः मैं मैम्बर साहैंबान को बताना चाहता हूं कि जो 10 लाख रुपया रखा गया है, वह पार्कों की देख रेख के लिये ही रखा गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या 805

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री आत्मा सिंह गिल, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे,

Power Sub-Station at Bahalgarh

***727. Shri Maha Singh :** Will the Minister tor Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up a New Power Sub-Station at Bahalgarh: and

(b) if So, the time by which the aforesaid power sub-station is likely to be set-up

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) No:

(b) Does not arise.

श्री महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, बहालगढ के चारों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है और गांवों के ट्यूबवल्ज को बिजली नहीं मिलती क्योंकि इंडस्ट्री साइड में हैवी लोड चलता है। इसलिये क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिस के तहत देहात में उचित बिजली सप्लाई कर दी जाए?

Shri Verender Singh : A 33 KV sub-station at village Bahalgarh in Rai Constituency of Sonepat District was set up over 'five years back. The . installed capacity of this sub-station was 4 MVA 33/ II K.V. Till May, 1987 the load of this sub-station was well contained but in May, 1987 it recorded a maximum demand of 4.8 MVA with the result the Board augmented its capacity to 9 MVA in July, 1988.

ई० जगपाल सिंहः चौधरी क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि 1989–90 में कहां कहां सब–स्टेशन मन्जूर हुए हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब जगह बताने के लिये एक लम्बी चौड़ी लिस्ट हो जायेगी, नही बता पाऊंगा परन्तु. टोटल इनको बता देता हूं। During 1989-90, it is proposed to spend

Rs. 50 crores on transmission works in the State to complete '''three new 220' KV sub-stations at Panchkula, Bhiwani and Palwal, nine 132 KV substations, four 66 KV Sub-stations and twenty 33 K.V sub-stations.

श्री हीरा नन्द आर्यः मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रदेश में ऐसे कितने सब–स्टेशन्ज हैं जो तीन तीन चार चार साल से ओवर –लोडिड हैं और उनको कब तक औगमैंट कर पायेगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः औनरेबल मैम्बर ने पूछा हैकि कितने सब्र–स्टेशंज सारे प्रदेश? में ओवर–लोडिड हैं। लोड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, ज्यों ज्यो कनैक्शन दिये जातेहैं। बोर्ड की कोशिश यही होती है कि अगर अधिक लोड बढ़ जाये तो उसे फौरी तौर पर औगमैंट कर दिया जाये या कोई विशेष ट्रांसफार्मर ऐड कर दिया जाये। इस समय कोई विशेष शिकायत बोर्ड के पास नही आई है। अगर श्री हीरा नन्द जी के नोटिस मेंकोई ऐसा केस हैतो वह बता दें उसको ठीक, करवादिया जायेगा।

श्री मांगे रामः मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या बहादुरगढ़ का नाम उन नौ 132 के० वी० सब–स्टेशन्ज में शामिल है, जो 1989–90 में ये स्थापित करने जाने है? **श्री वीरेन्द्र सिंहः** नाम की लिस्ट इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री शिव प्रसादः अम्बाला, एक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है। क्या अम्बाला शहर का नाम उन चार 66 के० वी० के स्टेशन्ज में है जिन्हें ये स्थापित करने जा रहें हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैंने पहले ही अर्ज किया है कि नामों की लिस्ट मेरे पास नहीं है।

श्री महा सिंहः स्पीकर साहब, मेरे हल्के में बहालगढ के साथ लगता हुआ कुन्डली भी बड़ा भारी इन्डस्ट्रीयल काम्पलैक्स है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि वहां पर कोई बड़ा सबस्टेशन बनाने का प्रावधान है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः कुण्डली में पहले से ही सब–स्टेशन बना हुआ है और 33 के० वी० का है। डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में जितने पावर स्टेशंज हैं और जहां जहां से पावर सप्लाई हो रही है उसकी इन्फरमेशन मैं इन्हें दे देता हूं।

The power in Sonipat District is disbursed through following sub-stations-

1.	132 KV	(i) Gannaur (ii) Sonipat (iii) Gohana.
2.	33 KV	(i) Farmana (ii) Gohana (iii) Kailana, (iv) Kathura (v) Kharkhoda (vi) Kundli (vii) Larsoli (viii) Murthal (ix) Paper Mill Bahalgarh (x) Rai (xi) Sonipat (old City) (xii) Tajpur (xiii) Suraj Steel (Industrial Area Sonipat).-13 Nos.

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि गत मास के दौरान विशेष कर फरीदाबाद, गुड़गांव और दो अन्य जिलों में जो बिजली की कमी रही है, उसको दूर करने के लिये क्या सरकार इस किस्म के और सब–स्टेशंज खोलेगी या कोई और योजना बनायेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, पिछले लगभग 20–25 दिन या चार हफते से हरियाणा प्रान्त में, मौजूदा सरकार बनने के पश्चात् पहली बार कुछ बिजली की कमी महसूस कीं गई। जैसा मैंने लैजिस्लेचर पार्टी में सदस्यों को बताया था कि पौंग डैम में आग लग गई थी. और उसकी वजह से बिजली की सप्लाई हमें कम हो गई थी।। लेकिन पिछले दों–तीन दिन से सप्लाई ठीक है और अगले दों–चार दिनों में बिल्कुल सही हो जायेगी। जो पलवल और फरीदाबाद का इलाका है वहां पर सब–स्टेशंज कमजोर होने की वजह से कोई दिक्कत नही है लेकिन मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए उन्हैं बता दू कि पलवल में 220 के०वी० का सब–स्टेशन बना रहैं हैं और उससे बिजली की सप्लाई की पोजीशन सारे फरीदाबाद में सुदृढ़ होगी।

श्री उदय भानः पलवल में 220 के० वी० का सब–स्टेशन जो बन रहा है यह कब तक शुरू हो जायेगा?

Shri Verender Singh : Latest by June, 1989

सेठ लछमन दास बजाजः पिछली बार काछवा में इन्होने खुद ही अनाऊंस किया था कि वहां पर 33 के० वी० का सबस्टेशन जल्दी लग जायेगा लेकिन वह अभी तक नहीं लगा। क्या उसके लगने की उम्मीद है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः मैं बजाज साहब के साथ काछवा गांव में गया था और वहां के लोगों ने इसके लिये माया की थी। मैंने कहा था कि मैं उसको ऐग्जामिन करवाऊंगा। वह ऐग्जामिन हो रहा है और अगर विभाग को उसकी जरूरत महसूस हुई तो वह जरूर बनेगा।

सरदार बूटाः स्पीकर साहब, मन्त्री जी एक दफा सीवन में गये थे और उन्होंने मेरी शादी के मौके पर यह कहा था कि 132 के० वी० सब–स्टेशन जरूर आपको दिया जायेगा। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या 9 सब–स्टेशनों में सीवन का नाम शामिल है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः माननीय सदस्य की शादी के अवसर पर मैं वहां पर गया था, बहुत खुशी का मौका था और ऐसे खुशी के मौके पर गमी की बात मैं कैसे कह सकता था? (हंसी)।

श्री रघु यादवः मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस समय महैंन्द्रगढ़ जिले में बिजली की स्थिति जो खराब है और किसान इस वजह से बहुत परेशान है, वह कब ठीक हो जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः माननीय सदस्य महैंन्द्रगढ़ कब गये थे इसका तो मुझे पता नही लेकिन अब अगर 13 तारीख को जाने के पश्चात उनको कोई कमी मिले तो मुझे बतायें। मैंने तो कहा है कि दों–तीन दिन से हालात सुधरी है।

Lining of Water courses

***787. Shri Mani Ram :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government for lining the water courses to irrigate the villages of Dabwali Constituency during the financial year 1989-90 ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Yes. water courses for a length of 0.50 lac rft are planned to be undertaken during 1989-90.

श्री मनी रामः स्पीकर साहब, यह जो 0.50 लाख आर०एफ० टी० पक्के खाल बनाने जा रहैं हैं, क्या ये सारे हरियाणा प्रान्त के हैं या डबवाली विधान सभा क्षेत्र के हैं?

श्री बीरेन्द्र सिंहः केवल डबवाली हल्के के हैं।

श्री दुर्गा दत अत्रीः स्पीकर साहब, जो आलरेडी पक्के खाल बनाये गए हैं उनमें से बहुत सारे गिर गए है। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि इसी साल उनकी मुरम्मत कर दी जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जो आलरेडी पक्के खाल बने हुए वे गिरे नहीं हैं, जगह–जगह से डैमेज हो गए हैं। सारे राज्य से बहुत सी शिकायतें आई हैं कि कुछ का बैड–लैवल ठीक नहीं है, कुछ अच्छा मैटिरियल न लगने की वजह से डैमेज हो गए हैं। यह बहुत भारी काम है। हम एक लिस्ट तैयार करवा रहैं हैं कि टोटल खाल ऐसे कितने हैं जो डैमेज हैं, जिनको रिपेयर करना पड़ेगा, या रि–मौडल करना पड़ेगा। यह लिस्ट तैयार होने के बाद देखेगे कि, उसकी ऐस्टीमेटिड कौस्ट क्या बनेगी, उसको देखकर फिर अगले साल कुछ न कुछ काम शुरू किया जायेगा।

श्री भागी रामः मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा सिरसा जिले में जो इस साल बाढ़ आने की वजह से खाल टूट गए हैं, क्या उनको बनाने में कोई प्राथमिकता दी जाएगी?

श्री बीरेन्द्र सिंहः मैंने पहले ही कहा है कि हम डैमेज्ड खालों की लिस्ट तैयार करवा ने हैं। ऐस्टीमेटिड कौस्ट को देखकर कोई प्रायरिटी फिक्स। करके काम शुरू करेंगे।

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या कुछ खाल ऐसे हैं जो टूट गए थे और ठीक किये जा रहैं हैं। क्या कुछ ऐसे खाल भी हैं जो पिछली सरकार के वक्त में बने थे और उनमें अभी तक पानी

भी नहीं चला? वे खाल न तो नये खालों की कैटेगरी में आते हैं और न ही पुराने की। क्या ऐसे खालों की डिटेलज बतायेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः जो इस्तेमाल ही नहीं हुए वे बनाये ही किस लिये गये थे। यह तो कोई बड़ा भारी घपला नजर आता है। अगर आप नोटिस में लायेंगे तो इन्कवायरी करायेगे।

कामरेड हरपाल सिंहः अभी यह कहा गया है कि मैटिरियल के घटिया होने की वजह से यह सारी गड़बड़ी हुई है। अभी भी कुछ नहरें पक्की बन रही हैं। उनके अन्दर ऐसा मैटिरियल प्रयोग हुआ है या हो रहा है तो क्या मंत्री महोदय उसकी इन्कवायरी करवाने को तैयार हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः आप यदि कोई ऐसी बात नोटिस में लायेंगे तो फौरी तौर पर सख्त से सख्त ऐक्शन लिया जायेगा।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो खाल अभी कच्चे पड़े है उनको पक्का करने के लिये क्या कोई प्रायरिटी फिक्स की जायेगी? क्या कोई ऐसी स्कीम पर भी विचार करेंगे कि जो खालें नई बननी हैं या डैमेज पड़ी हैं, अगर वहां के लोग खर्चे का एक चौथाई / एक तिहाई हिस्सा जमा करवा दें, तो क्या उनको बनाने में प्रायरिटी दी जायेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, सारे प्रान्त में 10 हजार वाटर कोसिज ऐसे हैं जिनकी लाईनिग करनी है और इनकी लम्बाई 40 हजार किलोमीटर बनती है। 1973– 74 से हमने वाटर

कोर्सिज की लाईनिंग का कार्य शुरू किया था। अब तक 4200 वाटर कोर्सिज जिनकी लम्बाई 17685 किलो मीटर है, की लाईनिंग हो चुकी है। जहां तक चौधरी बलबीर सिंह जी के सुझाव का ताल्लुक है कि अगर किसान अपने पल्ले से खर्चे का आधा पैसा दे दें या एक तिहाई दे दे तो उसको प्रायरिटी दे दी जायेगी या नही? ये शेयर होल्डर से हमें लिखवाकर दें, हम इसको ऐग्जामिन करेंगे और मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त करके उनको प्रायरिटी देने की कोशिश करेंगे।

श्री हजार चन्दः अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जो बाद पीड़ित एरिये के अन्दर खालों को मूरम्मत करने के लिये राशि दी गई थी जिसमें से 16 लाख रुपये सिरसा जिले के लिये रिजर्व थे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस 16 लाख रुपये के बारे में कोई रिपोर्ट हैं कि उससे कौन–कौन सी खालें रिपेयर की गई और किन–किन गांवों में की गई?

श्री वीरेन्द्र सिंहः इस समय इस प्रकार की कोई रिपोर्ट मेरे समझ नहीं आई।

कामरेड हरपाल सिंहः मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि अगर घटिया मैटिरियल लगने की कोई शिकायत है तो उनको बताई जाये। फतेहाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी अभी पक्की हो रही है। वहां पर जो सीमेन्ट, रेता या ईंट इस्तेमाल हो रही है उसका मेरे पास सैम्पल है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अगर आपके पास कोई ऐसा सैम्पल है तो वह मुझे अभी दे दें।

श्री अध्यक्षः सैम्पल लेने का एक तरीका होता है। जहां से सैम्पल लिया जाता है, वहां उसे सील कर दिया जाता है। आपके पास जो सैम्पल है उससे यह कैसे साबित होगा कि वह सैम्पल वाकई ही वहां का है? मंत्री महोदय ने पहले ही आश्वासन दिया है कि यदि कोई केस इस किस्म का आप उनके नोटिस में लायेंगे तो ये उसे ऐग्जामिन करवायेगे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यदि इनके पास कोई ऐसा सैम्पल है तो वह उसे हाउस में क्यों नहीं लाये? लगता है इनके पास ऐसा कोई सैम्पल नहीं है। (विघ्न) अगर स्पीकर साहब, आप इजाजत दें तो मैं अभी इनके साथ हो लेता हूं। अगर मुझे ये कोई ऐसा मैटिरियल देंगे तो उसको ऐग्जामिन करवा लेगे लेकिन तथ्य यह है कि ऐसीं कोई बात हैं नहीं।

श्री कुन्दन लाल भाटियाः मंत्री महोदय ने अभी कहा हैं कि कुछ नहरे/खालें घटिया मैटिरियल लगने की वजह से टूटी हैं। क्या यह उसकी इन्कवायरी करवाने के लिये तैयार हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः कोन से बिल्डिंग मैटिरियल की आप बात कर रहैं हैं। ये खालें तो बहुत पुरानी बनी हुई हैं।

श्री हीरा नन्द आर्यः मन्त्री महोदय के नोटिस में पहले भी यह बात लाई गई थी कि कार्यकारी अभियन्ता,

एम०आई०टी०सी० हिसार ने लाखों रुपये की बोगस पेमैन्ट की। पहले उस पेमैन्ट को रोक दिया गया था लेकिन बाद में रिलीज कर दिया गया। इस बिना पर उसे निलम्बित भी किया गया था लेकिन बाद में मामला रफा–दफा कर दिया गया था। क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह बात सही हैं?

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न मेन–प्रश्न से पैदा नहीं होता। आप कृपया बैठे।

Installation of Capacitors

***828. Shri Gurdial Singh Saini and Shri Hira Nand Arya** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether the Electricity Board has imposed any condition for the installation of capacitors on tubewells; if so, the date thereof; and

(b) whether any representation has been received regarding imposition of conditions; if so, the action taken thereon ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) Yes, the condition was imposed in July, 1981.

(b) No representation has been received by the Board.

श्री हीरा नन्द आर्यः क्या मंत्री महोदय जी बतायेंगे कि कितने उपभोक्ताओं ने कैपेसिटर्ज लगाए हु और कितनों ने नहीं लगाए हैं? जिन्होंने नहीं लगाए हैं क्या उनसे भी 5 रुपये प्रति हौर्स पावर प्रतिमाह वसूल किया जा रहा है? क्या इस कंडीशन को दूर करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः हरियाणा प्रदेश में टोटल ट्यूबवैल कनैक्शन 3 लाख 20 हजार दिए गए हैं और अब तक जिन्होंने कैपेसिटर्ज लगाए हैं, उनकी संख्या 1,71,387 है।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ये कैपेसिटर्ज कहां बनते हैं, क्या ये सरकारी कारखानों में बनते हैं, या किसी प्राईवेट फर्म से लिए जा रहैं हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः इसकी बहुत सारी फैक्टरीज हैं। 11 फैक्टरीज ऐसी हैं जिनको बोर्ड ने ऐप्रूव किया है और उनके प्रोडक्टस आई०एस०आई० मार्कड हैं। हमकिसानो को यह ऐडवाईज करते हैं कि कैपेसिटर इन 11 फैक्टरीज में से किसी एक से खरीदें।

श्री हीरा नन्द आर्यः क्या यह बात ठीक है कि जिन्होंने कैपेसिटर्ज नही लगाए हैं उनसे भी 5/– रुपये प्रति हौर्स पावर प्रति मास वसूल किये जा रहैं हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अगर इस तरह से वसूल किया जा रहा है तो गलत किया जा रहा है। आप मेरे नोटिस में लाएं, मैं ऐक्शन का।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः मैं जानना चाहूंगा कि जब से यह सरकार बनी है, इसने कितने ट्यूबवैल कनैक्शन रिलीज किए हैं? अब तक कितने कनैक्शन पैंडिंग हैं और उनको कब तक बिजली दे दी जाएगी?

श्री अध्यक्षः इस सवाल का जवाब औफ हैण्ड देना मुश्किल है, क्योंकि यह सवाल मेन सवाल से पैदा नहीं होता। आप कृपया बैठ– जाइये।

श्री भगवान सहाय रावतः जो कैपेसिटर्ज लगाए गए हैं, क्या इनको बिजली बोर्ड सप्लाई करता है या किसान खुद खरीदते हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः बिजली बोर्ड सप्लाई नहीं करता, किसान खुद खरीदते हैं।

Line Losses in the State

***814. @Shri Harnam Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the percentage of line losses occurred in the State during the period from 1st January 1987 to 19th June, 1987, 20th June, 1987 to 31st December, 1987 and 1st

January, 1988 to 31st December, 1988;

(b) the cost of the power generation per unit in Panipat Thermal Plant, Faridabad Thermal Plant and Hydel Project Yamuna Nagar; separately, at present; and

(c) the rate at which the Electricity is being purchased from Bhakra and other sources ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) & (b) , (c) : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) **The** line losses are computed on monthly basis. The percentage losses for the referred periods were as follows :—

1-1-1987 to 30-6-1987	18.2%
1-7-1987 to 31-12-1987	24.9%
1-1-1988 to 31-12-1988	24%

(b) The present cost of generation in paise per unit, project-wise, is :-

Panipat Thermal Project	83 . 67

Faridabad Thermal Project	99.44
Western Yamuna Canal Hydel Project	52.90

(c) The latest cost per unit of power available to the State from Common/Central Projects is :—

Project	Cost in paise/unit
Bhakra Complex	9.8
Singrauli Super Thermal	50
Baira-siul	38.27
Salal	55
Badarpur Thermal	80.38
Indraprastha Thermal	59.31

Metalled Roads

***824. Chaudhri Sri Krishan Hooda :** Will the Minister for P.W.D. & R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following metalled roads :-

1. from V. Katwara (Rohtak) to V. Kathura (Sonipat),

2. from V. Ladhot(Rohtak) to V. Kiloi (Rohtak) ; and

(b) if so, the time by which these are likely to be constructed ?

लोक निर्माण मन्त्री (श्री ओम प्रकाश भारद्वाज):

(क) 1 नहीं।

2. हां।

(ख) अस्वीकृत सड़क जो क्रमांक न. 1 पर है, के लिए समय नहीं बताया जा सकता।

किलोई से शिव मन्दिर किलोई तक सड़क पहले ही बनी हुई है जब कि आगे के भाग अर्थात लाढोत से किलोई शिव मन्दिर तक की सड़क मंजूर है और निर्माणाधीन हैं। यह सड़क धन राशि उपलब्ध होने पर जल्दी ही पूरी कर दी जायेगी।

चौधरी श्री कृष्ण हुड्डा: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि कटवाड़ा से कथूरा जो सड़क है, सरकार ने उसकी जमीन भी ऐक्वायर कर ली और मालिकान को पेमेन्ट भी कर दी लेकिन फिर भी यह अस्वीकार कैसे हैं?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाज: पहली सरकार ने इस का ऐस्टीमेट बनाया था, लेकिन कोई पैसा वगैरह खर्च नहीं हुआ था। जब दोबारा इसका ऐस्टीमेट रिवाईज किया गया था तो पहली

सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया था। स्पीकर साहब, अब यह सड़क री– सैक्शन हो गई है। अगर श्री हुड्डा साहब इसे दोबारा बनवाना चाहते हैं तो यह मन्जूर कर ली जाएगी।

श्री मांगे रामः स्पीकर सर, लोहामाजरा गाँव में मस्ती जी गए थे और लोहामाजरा से सुखता तक की सड़क का ऐलान करके आए थे। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि वह कब तक बन जाएगी?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः माननीय सदस्य ने सड़क की बात कही थी और इनका इसके बारे में बार–बार आग्रह है। स्पीकर साहब, यह सड़क मन्जूर हो चुकी है, लेकिन जैसे साधन होगें इसका कार्य चालू कर दिया जाएगा।

श्री मांगे रामः स्पीकर साहब, पिछली सरकार ने रोहतक जिले के साथ सड्कों के बारे में वड़ा अन्याय किया था, क्या मन्त्री जी उस अन्याय को दूर करेंगे?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि रोहतक जिले के साथ बड़ी भारी ज्यादती हुई थी। मैं चौधरी मांगे राम जी को यह बताना चाहूंगा कि सबसे पीछे चौधरी श्री कृष्ण हुड्डा का बहादुरों का हल्का किलोई है, जिसमें सारे हल्के की सड्कों की लम्बाई सिर्फ 120 किलोमीटर है जबकि बहुत से हल्कों की सड्कों की लम्बाई 400 किलोमीटर से ज्यादा है। स्पीकर साहब, रोहतक में दूसरे नम्बर पर मेरा हल्का

हसनगढ है, जिसकी सड्कों की लम्बाई 120 किलोमीटर ही है और तीसरे नम्बर पर माननीय मुख्य मन्त्री जी का हल्का मेहम है, जिसमें सड़कों की लम्बाई 152 किलोमीटर है। आप सब इससे भलीभान्ति अन्दाजा लगा सकने हैं कि कितना पक्षपात रोहतक जिले के साथ हुआ है। इसको स्पीकर साहब, हमें कम्पनसेट करना ही पड़ेगा।

चौधरी श्री कृष्ण हुड्डाः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या किलोई हल्के को प्रायरिटी दी जाएगी?

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, इसका जवाब पहले ही मन्त्री जी दे चुके हैं।

श्री कान्ति प्रकाश भल्लाः स्पीकर साहब, मन्त्री जी मेरे हल्का कालका में कई दफा गए हैं और एक बार उन्होंने रामगढ़ की सड़क बनाने के बारे में अनाऊंसमैन्ट की थी और साथ ही कालका लिंक रोड बनाने के बारे में भी कहा था। क्या उनका उन सड्कों के बनाने के बारे में कोई विचार हैं?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, यह तो हम से बहुत आगे हैं। जो इलाके काफी पीछे हैं, पहले हमें उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा।

श्री महा सिंहः स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने अभी फरमाया था कि पिछली सरकार ने रोहतक जिले के साथ बड़ी नाइन्साफी की थी। मैं आपके द्वारा इनके नोटिस में लाना चाहूंगा कि इसी

तरह सोनीपत जिले के साथ भी उस सरकार ने बड़ी नाइन्साफी की थी। क्या मंत्री जो बताएंगे कि सोनीपत जिले को भी यह कम्पनसेट करेंगे?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, इस पर जरूर विचार किया जाएगा। लेकिन मैं इनको बता दूं कि इनका इलाका हमारे इलाके से काफी आगे है क्योंकि इनके हल्का राई में 174 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी अभी हल्कावाईज बता रहैं थे कि कितनी सड़कें बनी हैं। हरियाणा में कुछ ऐसे हल्के हैं जिनमें 100 से भी ज्यादा गाँव हैं। अभी मन्त्री जी 120 किलीमीटर सड़क बनाने का जिकर कर रहैं थे, इसके बारे में निवेदन है कि एक हलके में 30–30 और 40– 40 गाँव हैं और गाँव भी बहुत बड़े–बड़े हैं। उदाहरण के रूप में सिरसा डिस्ट्रिकट में दडवा, ऐलनाबाद गाँव हैं। इसी तरह से रोड़ी कास्टीचूऐंसी की बात है। वहां 100 से भी०पर गांव हैं। अध्यक्ष महोदय, कुदरती तौर पर उनके किलोमीटर ज्यादा होमे। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि सड़कें बनाने का इनका इसके अलावा और क्या क्राइटेरिया हैं?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, श्री भागी राम जी ने क्राइटेरिया पूछा है। क्राइटेरिये के हिसाब से सिरसा जिला पहले ही आगे है। 308 किलोमीटर इनके यहां सड़क बन चुकी है तथा 81. 94 किलोमीटर और सैकंशंड हैं।

श्री जय नारायण खुंडिया: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने खुद माना है कि रोहतक जिले के साथ पिछली सरकार ने बहुत भेदभाव किया है। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि अब रोहतक जिले की कितनी सड़कें सैक्शन की गई हैं?

श्री अध्यक्ष: यह जवाब पहले ही आ चुका है कि जिन हल्कों मे सड़कें कम बनी हैं, उनको प्रायरिटी दी जाएगी। हर एक कांस्टीच्चुएंसी के बारे में इस वक्त इन्फर्मेशन देना पौसिबल नहीं होगा।

श्री कुन्दन लाल भाटिया: क्या मन्त्री जी बतायेगे कि फरीदाबाद के अन्दर कितनी सड़कें बन गई हैं और आगे का क्या प्रोग्राम है?

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न रैलेवेंट नहीं है। भाटिया साहब आप बैठिए।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, बाढ़ के दौरान काफी सड़कें डैमेज हुई हैं और कई जगहों पर काम चालू नहीं हुआ जिससे सड़कें और ज्यादा खराब होती जा रही हैं। अम्बाला से जींद रोड पर कई जगह सड़क टूटी हुई है और यातायात में बड़ा नुक्सान होता है। क्या मन्त्री जी बताएगे कि इनको कब तक ठीक कर दिया जाएगा?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाज: स्पीकर साहब, मैं परसों भी जींद से यहां तक की सड़क देखता आया हूं और वहां पर काम

चालू है। अगर किसी सड़क पर काम चालू नहीं हुआ हो तो ये मुझे बता दें, मैं उसे देख लूंगा।

श्री बलवीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, जो आलरेडी सैंक्शंड रोड्ज थीं, उन में हिसार जिले की कितनी रोड्ज डी–सैक्शन हुई हैं?

श्री अध्यक्षः यह प्रश्न मेन सवाल से पैदा नहीं होता, आप कृपया बैठिए। हर एक सवाल का जवाब औफ–हैंड देना मुश्किल है।

श्री उदय भानः स्पीकर साहब, जो सड़कें सैक्शन हुई हैं, उन पर कब से काम शुरू होने जा रहा है और कब तक पूरा हो जाएगा?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, इन्होंने बड़ा टेढ़ा सवाल कर दिया है। रोड कमेटी ने, स्पीकर साहब, 17 करोड़ रुपये की सड़कें मंजूर की थीं और इस साल का सारा बजट पांच करोड़ का है। स्पीकर साहब, जैसे–जैसे हमारे पास फण्डज की गुंजाइश है, वैसे वैसे काम जारी है।

श्री भगवान सहाय रावतः क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि रोड कमेटी के कौन–कौन से सदस्य थे? उनके हलके में कितने किलोमीटर सड़कें बननी तय हुई हैं और मेरे हलके में कितनी तय हुई है?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः उस कमेटी में आई० पी० एम०, डा० कृपाराम पूनिया, श्री उदयभान तथा भागी राम जी मेम्बर थे। उस में बहुत व्य–छी तरह से हर कास्टीचूएंसी पर विचार किया गया कि आलरेडी कितनी सड़कें बन गई हैं और कितनी और जरूरी हैं जो बननी चाहिएं। इस बारे में जैसी भी कमेटी ने सिफारिशें की हैं, वे सिफारिशें माननीय मुख्य मन्त्री जी के सामने पेश कर दी गई थीं। जैसे जैसे फण्डज होंगे, सरकार कार्य शीघ्र शुरू कर देगी।

श्री भगवान सहाय रावतः स्पीकर साहब, मेरा प्रश्न यह णै कि कमेटी के मैम्बर्ज के हल्कों में कितनी सड़कें स्वीकृत की गई हैं और मेरे हल्के हथीन में कितनी की हैं? इसका जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्षः यह सवाल हथीन से ताल्लुक नहीं रखता। आप बैठिए।

Enhancement in Electricity Tarriff

***705. Shri Mangal Sein@ Shri Kundan Lal Bhatia :** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state—

(a) whether the rates of security deposit and Electricity Tariff were enhanced during the year 1988, if so, the category-wise details thereof ; and

(b) whether it is a fact that the tariff was subsequently reduced in case of certain categories of

consumers, if so, the details thereof ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) and (b) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Board revised the sccurity deposit rates for meters as well as energy consumption with effect from 1st January, 1988 as follows :—

(A) SECURITY FOR ENERGY METERS

	Cetegory of Consumers	Previous rates in Rs.	Revised rates in Rs. w.e.f. 1-1-1988
1 .	DOMESTIC SUPPLY		
(a)	Connected load upto 1 KW single phase	20	50
(b)	Connected load above 1 KW		
(ii)	Single phase	45	150
(ii)	Three phase	300	350
2.	COMMERCIAL SUPPLY		

(a)	Connected load upto I KW single phase	20	100
(b)	Connected load above 1 KW		
(i)	Single phase	50	150
(ii)	Three phase upto 50 KW	300	350
(iii)	Three phase above 50 KW	1000	2000
3.	AGRICULTURAL SUPPLY		
(a)	Upto 20 KW	50	100
4.	INDUSTRIAL SUPPLY		
(a)	Small power upto 20 KW	75	350
(b)	Medium supply		
(i)	Upto 50 KW	300	500
(ii)	Above 50 KW	1000	1000
(iii)	LT supply with CTs		2000
(iv)	HT supply with CT/PT	—	7500
(c)	Large Supply		
(i)	HT connection	Rs. 50 per KW with minimum of Rs. 2500 and max. of Rs.	Rs. 50 per KW with minimum of Rs. 2500 and max. of Rs. 5000

		5000	
(ii)	Upto 200 KW	—	7500
(iii)	Above 200 KW		10000
5.	BULK SUPPLY		
(a)	Upto 50 KW (LT supply)	300	500
(b)	Above 50 KW (LT supply)	1000	1000
(i)	LT supply with CT		2000
(ii)	HT supply	Rs. 50 per KW with min. of Rs. 2500 & max. of Rs. 5000	7500
6.	STREET LIGHT	As applicable for Bulk	supply.
(B)	SECURITY FOR SUPPLY OF ENERGY		
1.	DOMESTIC SUPPLY.		
(a)	Connected load upto 1 KW	20	30
(b)	Connected load above 1 KW	30 per KW or part thereof	45 per KW or part thereof
2.	COMMERCIAL SUPPLY		
(a)	Connected load upto 1 KW	40	60

(b)	Connected load above 1 KW	100 per KW or part thereof	150 per KW or part thereof
3.	AGRICULTURAL SUPPLY		
	Upto 20 KW	30 per KW or part thereof	30 per KW or part thereof
4.	INDUSTRIAL SUPPLY		
(a)	Small power upto 20 KW	30 per KW or part thereof	50 per KW or part thereof
(b)	Medium supply	100 per KW or part thereof	150 per KW or part thereof
(c)	Large supply	100 per KW or part thereof	150 per KW or part thereof
5.	BULK SUPPLY	100 per KW or part thereof	150 per KW or part thereof
6.	STREET LIGHT	200 per KW or part thereof	200 per KW or part thereof

(C) The Tariff for agricultural and domestic supply was revised with effect from 1-9-88 as follows :—

Name of category	Rates before 1-9-88	Rates after 1-9-88
DOMESTIC SUPPLY		
1st 40 Units	36 P/unit	50 P/unit

Next 60 units	40 P/unit	60 P/unit
Next 100 units	52 P/unit	75 P/unit
Above 200 units	60 P/unit	100 P/unit
AGRICULTURAL SUPPLY		
Metered supply (upto 20 KW or 26 BHP)	Energy charges @ 25 P/unit Plus Rs. 4 per BHP per month	Energy charges 30 P/unit Plus Rs. 4 per BHP per month
Flat rate (upto 20 KW or 26 BHP)	Energy charges@Rs. 20per BHP per month Plus Rs. 4 per BHP/ month	Energy charges Rs. 25 per BHP per month+4 per BHP/ month.

(b) The tariff for agricultural sector was revised from 25 P/unit to 35 P/unit in respect of motered tubewells and Rs. 20 per BHP to Rs. 30 per BHP in respect of unmetered tubewells w.e.f. 1st Sept., 1988. However, on representation by farmers that their capacity to bear additional burden had been eroded due to successive drought/floods, the State Govt. intervened and the revised tariff was reduced to 30 P/unit and Rs. 25 per BHP in case of metered and unmetered tubewells respectively.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन्होंने डोमैस्टिक सप्लाई के

टैरिफ में जो बढ़ौत्तरी की है, जैसे फस्ट 40 यूनिट पर 36 पैसे से 50 पैसे यूनिट, नैक्स्ट 60 यूनिट्स पर 40 पैसे से 60 पैसे यूनिट, नैक्सट 100 यूनिट्स पर 52 पैसे से 75 पैसे यूनिट और 200 यूनिट्स से०पर 60 पैसे से 100 पैसे यूनिट और मेरा कहना मान कर ऐग्रीकल्चर पर इन्होंने टैरिफ कम किया है, क्या जनता दल के अध्यक्ष की बात मानते हुए शहरों में भी टैरिफ कम कर देंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः कोई औचित्य नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, घरेलू आपूर्ति के लिये इन्होंने रेट 36 पैसे से 50 पैसे तथा 40 पैसे से 60 पैसे, 52 पैसे से 75 पैसे और 60 पैसे से 100 पैसे प्रति यूनिट किया है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ये बिल जो दिए जाते हैं, ये पिछले दो तीन महीने की ऐवरेज निकाल कर फ्लैट रेट के हिसाब से दिए जाते हैं या हायर स्लैब सिस्टम के हिसाब से दिये जाते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यह धारणा गलत है कि क्योंकि सप्लाई की बिलिंग बाई मंथली हो रही है इसलिए जो स्लैब महीने से बढ़ जाता है उसमें कंज्यूमर को अधिक देना पड़ता है। बिलिंग मंथ के आधार पर होती है। उस महीने में जो उसका सलैब बनता है उसको फिक्स कर देते हैं। अगले महीने में जो सलैब बनेगा उसके हिसाब से बिलिंग होगी। अगर कहीं किसी कंज्यूमर को बिलिंग में शक है और वह यह समझता है कि दो

महीने का इकट्ठा रेट लगाया है, तो गलत है। वह उसे महकमे से ठीक करवा सकता है। अगले दो महीने की बिलिंग हम इसलिये कर रहैं हैं ताकि हर महीने हमें बार बार रिकवरी न करनी पड़े। साल में हम छः बार रिकवरी करते हैं।

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐग्रीकल्चर सैक्टर में पहले रेट 25 पैसे से 35 पैसे और बाद में रिवाइज होकर 30 पैसे होने के कारण जिनसे०चे रेट पर पैसे लिये गये थे, क्या उनसे, जो ज्यादा पैसे लिए गए थे, वे उनको वापिस किये जायेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जहां–जहां ज्यादा पैसे लिये गए होंगे, वे उनको रिफण्ड हो जायेंगे या बिलों में ऐडजस्टमैंट हो जाएगी।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने अभी फरमाया था कि कोई औचित्य नहीं है? क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जस्टिफिकेशन की क्या परिभाषा है और किस बात से जस्टिफिकेशन होगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः डा० साहब का सवाल यह था कि जैसे ऐग्रीकल्चर सैक्टर में बात मानी गई, क्या दूसरे सैक्टर में भी बात मानेंगे? देंने कहा कोई औचित्य नहीं है। इसलिये औचित्य नहीं है क्योंकि हर तरफ से रेट्स की बढ़ोत्तरी हो रही है। कोयले की कीमत बढ़ गई, फ्रेट बढ़ गया है, आयल की कीमत बढ़ गई है

तथा ऐम्पलाईज की तनखाहैं बढ़ गई हैं। इस प्रकार से जनरेशन की कोस्ट०पर चली गई। इसीलिये टैरिफ की रिवीजन जरूरी हो गई है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, औचित्य की परिभाषा करते हुए मन्त्री महोदय ने कहा है कि कोस्ट औफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसे ऐग्रीकल्चर सैक्टर में टैरिफ कम करने का औचित्य था उसी तरह कमर्शियल और डोमैस्टिक सैक्टर में टैरिफ कम करने का औचित्य क्यों नहीं है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, किसान की फाइनैंशियल हालत देखते हुए उसको सारे देश में बिजली सबसेडाइज्ड रेट पर देते हैं। ड्रौट का ईयर था, इसलिये सोचा गया कि जो बढ़ौत्तरी की गयी है उसमें कुछ कमी कर दी जाए। इस तरह से किसान को भी छोड़ा नहीं गया बल्कि 5 पैसे की बढ़ौतरी उनके रेट में भी की गई।

Mr. Speaker : Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर

Telephone Bills of the Council of Ministers

***701. Shri Hira Nand Arya :** Will the Chief Minister be pleased to state the total amount of expenditure incurred on account of bills of Telephone installed at the residences and offices of the Chief Minister, Deputy Chief Minister and

each of the Minister, Minister of State, Deputy Minister and Chief Parliamentary Secretary during the last three years ?

Chief Minister (Chaudhri Devi Lal) : A statement containing the requisite irmformation is laid on the Table of the House.

Statement

Statement showing the total expenditure incurred on account of bills of Telephones installed at the residences and Offices of the C.M., Deputy C.M. and each of the Minister, Minister of State, Dy. Minister and C.P.S. during the last three years (from 1-1-86 to 15-1-89).

Sr. No.	Name & Designation	Amount of Telephone Bills	Remarks
1	2	3	4
	S/Sh./Smt.		
1.	Bhajan Lal, Ex. C.M.	1,23,217.45	(1-1-86 to 4-6-86)
2.	Bansi Lal, Ex. C.M.	1,93,649.20	(5-6-86 to 20-6-87)
3.	S.S. Surjewala. Ex. IPM	2,38,308 . 75	(1-1-86 to 19-6-87)
4.	Col. Ram Singh, Ex. TM/DM	1,22,437.95	(1-1-86 to 1-6-87)
5.	Rajinder Singh, Ex. DM	34,945. 35	(1-1-86 to 4-6-86)

6.	Parsanni Devi, Ex. PHM/AM	2,06,093.65	(I-I-86 to 19-6-87)
7.	Shakuntla Bhagwaria, Ex. IM	28,345 . 50	(1-1-86 to 4-6-86)
8.	Katar Singh, Ex. ETM/FM	1,54,785.30	(I-1-86 to 19-6-87)
9.	Kalyan Singh, Ex. FSM	17,658 .05	(1-1-86 to 4-6-86)
10.	Amar Singh Dhanak, Ex. PWM/TM	1,23,411.55	(1-1-86 to 19-6-87)
11.	Sagar Rani Gupta, Ex. FM	24,971.65	(1-I-86 to 4-6-86)
12.	Goverdhan Dass Chauhan, Ex. HAM	2,16,002.75	(1-1-86 to 19-6-87)
13.	Siri Krishan Dass, Ex. IM	I,15,160.65	(5-6-86 to 19-6-87)
14.	Phool Chand, Ex. PWM	87,613.20	Do
15.	Sharda Rani, Ex. EM	1,44,936.15	Do
16.	Tayyab Hussain, Ex. HM	73,438.20	(8-12-86 to 19-6-87)
	Minister of State		
17.	Lal Singh, Ex. MAH	32,483 .00	(1-1-86 to 4-6-86)
18.	Piara Singh, Ex. MC	1,15,839.90	(1-1-86 to 19-6-87)
19.	Rajesh Sharma, Ex. MLE	1,30,196.95	(1-1-86 to 19-6-87)
20.	Chanda Singh, Ex-MT	53,346.75	(1-1-86 to 4-6-86)
21.	Lachhman Dass Arora, Ex-	70,312.35	(1-1-86 to 19-6-87)

	MLG		
22.	Jagdish Nehra, Ex-ME	94,803.35	(1-1-86 to 19-6-87)
23.	Kartar Devi, Ex-MHA/MSW	79,133.20	(I-1-86 to 19-6-87)
24.	Jaswant Singh Chauhan, Ex-MDD	14,966.15	(1-1-86 to 4-6-86)
25.	O.P. Mahajan, Ex-MLG	22,711.55	(1-1-86 to 4-6-86)
26.	Shakrulla Khan, Ex-MIP	I2,448.20	(1-1-86 to 4-6-86)
27.	Nirmal Singh, Ex-MR	I,20,281.25	(5-6-86 to 19-6-87)
28.	A.C. Chaudhary, Ex-MLG/MPH	87,806.15	(5-6-86 to I9-6-87)
29.	Inder Jit Singh, Ex-MFC	88,444.65	(5-6-86 to 19-6-87)
30.	Om Parkash, Ex-MFW	24,483.60	(8-12-86 to 19-6-87)
31.	Roshan Lal Tiwari, Ex-CPS	13,511.00	(I-1-86 to 4-6-86)
32.	Devi Lal, CM	6,56,442.15	(21-6-87 to 15-I-89)
33.	B.D. Gupta, Dy. CM	3,60,597.05	(21-6-87 to 15-1-89)
34.	Verender Singh, IPM	1,63,696.80	(21-6-87 to 15-I-89)
35.	K.R. Punia, IM	3,49,965.80	(21-6-87 to 15-I-

			89)
36.	Suraj Bhan, RM	1,76,340.50	(21-6-87 to 15-1-89)
37.	Sampat Singh, HM	3,96,477.45	(21-6-87 to 15-1-89)
38.	Khurshid Ahmed, EM (now Ex-EM)	3,19,436.00	(2-9-87 to 15-1-89)
39.	Hukam Singh, DM	I,30,999.85	(11-8-87 to 15-I-89)
40.	Ram Bilas Sharma, PHM	2,16,319.00	(11-8-87 to 15-1-89)
41.	Kamla Verma, HAM	1,99,263.00	(2-9-87 to 15-1-89)
42.	Rao Laxmi Narain, ITM	1,71,578.10	(11-8-87 to 15-1-89)
43.	O.P. Bhardwaj, PWM	1,62,027.50	(11-8-87 to 15-1-89)
44.	Sushma Swaraj, FSM	I,58,227.65	(17-1-88 to 15-1-89)
45.	Tayyab Hussain, AM	1,72,207.00	(11-4-88 to 15-1-89)
46.	Rao Ram Narain, ETM	I,17,463.60	(11-4-88 to 15-1-89)

47.	Parma Nand, FWM	1,68,849.10	) (18-7-87 to 15-1-89
48.	RaghubirSingh, MC	2,19,500.85	(11-8-87 to 15-1-89)
49.	Dharm Vir Singh, MT	4,31,716.10	(18-7-87 to 15-1-89)
50.	Subhash Katyal, MHDD	2,16,172.35	(11-8-87 to 15-1-89)
51.	Balbir Singh, MEL	1,06,893.80	(2-9-87 to 15-1-89)
52.	Azmat Khan, MAH	1,26,722.45	(11-8-87 to 15-1-89)
53.	Sita Ram Singla, MSC	1,42,883.85	(17-9-87 to 15-1-89)
54.	Nar Singh Dhanda, MSJ	1,46,361.15	(2-9-87 to 15-1-89)
55.	A. S. Bhadana, MLG	4,327 . 35	(15-10-88to15-1-89)
56.	Hari Singh Saini, MCA	Bill not received	2-11-88
57.	Lachhman Singh Kamboj, DMPW	73,402.50	(11-4-88 to 15-1-89)
58.	Sachdev Tyagi, DMIP	1,01,935.00	(11-4-88 to 15-1-

			89)
59.	Dhir Pal Singh, CPS	1,05,149.00	(17-1-88 to 15-I-89)
	Ex. State	Ministers	
60.	Manphool Singh, Ex. MJ	1,00,952.65	(18-7-87 to 15-1.88)
61.	Maha Singh, Ex. MDD	20,742.45	(2-9-87 to 15-1-88)
62.	Narbir Singh, Ex. MPS	48,829.15	(2-9-87 to 15-1-88)
	Ex. Chief Parliamentary	Secretary	
63.	Ran Singh Mann	67,422.40	(18-7-87 to 15-1-88)

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने आज एक काल अटैन्शन मोशन दी है। ए० एस० आई० बलबीर सिंह और हरि राम चण्डीगढ़ में कुछ लोगों को पकड़ कर ले गए और उनके साथ धींगामस्ती की जिसको अखबारों ने भी कंडैम किया है।

श्री अध्यक्षः इसे कंसीडर किया जा रहा है।

श्री रघु यादवः स्पीकर साहब, मैंने एक हाफ एन आवर डिस्कशन का नोटिस दिया है, उसका क्या बना?

श्री अध्यक्षः वह मैंने डिस–अलाऊ कर दिया है।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैंने भी एक नोटिस दिया हुआ है।

श्री अध्यक्षः वह कंसीडर हो रहा है।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, अखबारों में आया है कि केन्द्रीय सरकार सी० बी० आई० के थ्रू हरियाणा सरकार के खिलाफ इन्फर्मेशन कुलैक्ट करके प्रैजिडेट रूल लगाने की साजिश कर रही है

श्री अध्यक्षः आपने इसके लिये कोई नोटिस दिया है?

श्री हीरा नन्द आर्यः नोटिस तो नहीं दिया है।

श्री अध्यक्षः कृपया आप बैठिए। जब कोई नोटिस आयेगा तो उसको देख लिया जायेगा।

बिजनैस ऐं डवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट

श्री अध्यक्षः अब मैं वेरियस बिजनैस के बारे में बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी द्वारा फिक्स किया गया टाईम टेबल रिपोर्ट करता हूं –

"The Committee met at 9.00 A.M. on Wednesday, the 8th March, 1989, in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in Session, shall meet on Monday, at 2.00 P.M., and adjourn at 6.30 P.M. and on

Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put.

The Committee also recommends that on Wednesday, the 15th March, 1989 the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the list of Business for the day.

The Committee, after some discussion, also recommends that the Business from 8th March, to 10th March and from 13th March to 15th March. 1989 be transacted by the Sabha as follows :—

Wednesday, the 8th March, 1989 (9-30 A.M.)		Questions Hour.
		Presentation and adoption of the Second Report of Business Advisory Committee.
		Motion under Rule 30.
		Presentation of Budget for the year 1989-90.
Thursday, the 9th March, 1989 (9.30 A.M.)		Questions Hour.
		Papers to be laid on the Table of the House.
		General Discussion on the Budget for the year 1989-90.

Friday, the I0th March, I989 (9.30 A.M.)		Questions Hour.
		Resumption of General Discussion on the Budget for the year 1989-90 and reply by the Finance Minister.
Saturday, the 11th March, I989		Off-day.
Sunday, the 12th March, 1989		Holiday.
Monday, the 13th March, 1989 (2.00 P.M.)		**Questions Hour.**
		Discussion and Voting on Demands for Grants on the Budget for the year 1989-90.
Tuesday, the I4th March, I989 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Presentation of Assembly Committees Reports.
	3.	The Haryana Appropriation Bill, 1989 in respect of Supplementary Estimates for the year 1988-89.
	4.	Legislative Business.

Wednesday, the 15th March, 1989 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Presentation of Assembly Committees Reports.
	3.	Motion under Rule 15 regarding Non-Stop Sitting.
	4.	Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha Sine-die.
	5.	The Haryana Appropriation Bill, 1989 in respect of the Budget for the year 1989-90.
	6.	Legislative Business.
	7.	Any other Business."

अब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर यह प्रस्ताव करेंगे कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की सैकिण्ड रिपोर्ट में दी गई रिकमैन्डेशन से सहमति प्रकट करता है।

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, **I** bcg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ –

कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की सैकिण्ड रिपोर्ट में दी गई रिकमैन्डेशन्ज से सहमति प्रकट करता है।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, आज यह बात सुनकर और देखकर मैं हैरान रह गया कि बजट पर डिस्कशन एक दिन की होगी।

श्री अध्यक्षः नहीं, दो दिन डिस्कशन होगी। इसके अलावा एक दिन डिमांड्ज पर डिस्कशन होगी। इस तरह से तीन दिन हो जाएंगे। फिर ऐप्रोप्रिएशन बिल पर भी मैम्बर्ज बोलेंगे।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैम्बरों के लिए एक बजट सैशन ही ऐसा सैशन होता है जिसमें अपनी कांस्टीच्यूऐसी की प्रोब्लम्ज और पब्लिक की जो ग्रीवैंसिज हैं, इशूज हैं, उन को रेज किया जा सकता है। स्पीकर साहब, पहले 20 तारीख तक सैशन चलना था जिसको अब 15 तारीख तक करदिया गयाहै। ऐसी क्या जल्दी है? मन्त्री परिषद को तो चण्डीगढ़ में ही रहना है, हम को भी कुछ समय मिल जायेगा। हम कुछ तैयारी करके आयेंगे और कुछ बात कहैंगे। मैं समझता हूं कि डैमोक्रैसी में जब गवर्नमेंट बाई डैलीब्रेशन्ज होती है तो डैलीब्रेशन का पूरा मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्षः डा० साहब दो दिन तो बजट पर डिस्कशन होनी है फिर डिमांडज पर डिस्कशन होगी और उसके बाद ऐप्रोप्रिएशन बिल भी आयेगा।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, दो दिन में तो सिर्फ मुश्किल से 5–6 लोग ही बोल पायेगे।

श्री अध्यक्षः पांच छः कैसे बोल पायेंगे? ज्यादा लोगों को मौका दिया जायेगा।

श्री रघु यादव (रिवाड़ी): अध्यक्ष महोदय, सप्ताह में वीरवार को गैर–सरकारी संकल्प पर डिस्कशन करने का समय होता है और इस समय सदन के सम्मुख एक प्रस्ताव तो पहले से ही अंडर डिस्कशन है। इसके इलावा, हीरा नन्द आर्य जी का प्रस्ताव नशाबन्दी के बारे में और मेरा क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए अहीरवाल डिवैल्पमेंट बोर्ड की स्थापना के बारे में है। इसलिए गैर–सरकारी संकल्प वाले दिन को सरकारी कामकाज के लिए न लिया जाए और उस दिन गैर सरकारी संकल्प ही डिस्कस किए जाएं।

श्री अध्यक्षः आप कृपया बैठिए। आप की बात आ गई है।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, मौजूदा सरकार ने 20 जून, 1987 से जिम्मेवारी सम्भाली है। तब से जो भी सैशन हुआ वह दूसरे सैशन के मुका– बले में हमेशा लौंगेस्ट रहा है और इस बार भी हमने बाकायदा डैमोक्रेटिक ट्रैडीशज को कायम रखने के लिए एक महीने के सैशन का बिजनैस फिक्स करवाया था। माननीय सदस्यों को पता है 27

तारीख को एक दो घंटे के बाद सदन उठ गया, 28 तारीख को भी हम तकरीबन एक दो घंटे के बाद ही उठ गए। कल स्पीकर साहब, साढ़े ग्यारह बजे हाउस ऐडजर्न हो गया। इस प्रकार से जब कोई काम नहीं निकल पा रहा तो व्यर्थ में यहां बैठे रहैं, इससे अच्छा यह है कि हम पूरा टाईम काम करें। बजट की बहस कल से शुरू हो रही है और न हम बाहर जाएंगे और न आप बाहर जायेगे। बजट पर बहस के लिए दो दिन रखे गये हैं और फिर एक दिन डिमांड्ज के लिए भी मिलेगा। जहां तक रघु यादव जी की बात का ताल्लुक है, इनका रैजोल्यूशन तो तीसरे नम्बर पर था। अभी तो एक साल से एक ही रैजोल्यूशन, जो कसाईनमेंट टैक्स के बारे में है, पर ही डिस्कशन चल रही है और पता नहीं उस पर कितना टाईम और लगेगा। यह भी सुनने में आया है कि उसके बारे में पार्लियामेंट में कोई बिल आ रहा है। उसकी इम्पौटैंस कुछ थोड़ी सी यूं भी कम हो जाती है। इसके इलावा, सभी को यह भी पता है कि नूह का कई–इलैक्शन सिर पर है। महैंन्द्र प्रताप जी ने भी वहां जाना होगा, डा० साहब ने भी जाना है और हम भी जाना चाहैंगे। इस तरह हर पोलिटिकल आदमी उसमे हिस्सा लेने के लिए जाना चाहूंगा इस लिए में हाउस से प्रार्थना करूंगा कि इस रिपोर्ट को यूनानिमसली एडौप्ट किया जाए।

श्री महैंन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, इनकी बात से मैं इत्तफाक करता हूं, लेकिन स्पीकर

साहब, बजट की बहस के लिए दो दिन का समय मैं समझता हूं कम है, क्योंकि उस पर सभी मैम्बर्ज बोलना चाहैंगे। जैसे मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि एक रैजोल्यूशन चल रहा है और उसका खास फायदा भी नही है, तो ऐसे गैर जरूरी बिजनैस को कम कर के अगर एक दिन बजट के लिए और बढ़ा दिया जाए तो मैं समझता हूं, ठीक रहैंगा।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की सैकेण्ड रिपोर्ट में दी गई रिकमैन्डेशज से सहमति प्रकट करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः अब पार्लियामैन्टरी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 30 के तहत प्रस्ताव पेश करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, **I** beg, to move—

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 9th March, 1989.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ –

कि हरियाणा विधान सभा के रूल्ज औफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट औफ बिजनैस के रूल 30 को सस्पैंड किया जाये और थर्सडे, 9 मार्च 1989, को सरकारी काम किया जाए।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय इस प्रस्ताव के द्वारा हम से चाहते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन जो प्राईवेट मैम्बर्ज को अपनी बात कहने का मौका मिलता है उसको रद्द कर दिया जाए और उस दिन सरकारी काम किया जाए। इस सम्बन्ध में मैं हम्बली सबमिट करना चाहता हूं कि मेरा भी एक प्रस्ताव है जो लिस्ट पर तो नहीं है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। स्पीकर साहब, कसाईनमेंट टैक्स के बारे में जो रेजोल्यूशन है, वह भी बड़ा इम्पौर्टंट है लेकिन लोक आयुक्त का मामला पब्लिक लाईफ को क्लीन रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे सदन के नेता का यह नारा है कि भ्रष्टाचार बन्द हो और बिजली पानी का प्रबन्ध हो।

श्री अध्यक्ष: आपको उसका जवाब मिल गया होगा।

श्री मंगल सैन: मुझे नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष: मिल गया होगा। उसे मैंने डिस–अलाऊ कर दिया है क्योंकि उसके बारे में हाउस में भी चर्चा हो चुकी है और क्वैश्चन पर भी जवाब दिया जा चुका है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, वह तो बड़ा इम्पौर्टंट मामला था। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः डा० साहब, अब आप बैठिए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि हरियाणा विधान सभा के रूल्ज औफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट औफ बिजनैस के रूल 30 को सस्पैंड किया जायें और थर्सडे, 9 मार्च 1989, को सरकारी काम किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वर्ष 1989– 90 का बजट पश करना

श्री अध्यक्षः अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर ईयर 1989– 90 का बजट प्रेजैन्ट करेंगे।

उप–मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त): माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे गणमान्य साथियो, मैं लगातार दूसरे वर्ष इन बजट अनुमानों को प्रस्तुत करते हुये अपने को गौरवान्वित अनुभव करता हूं, क्योंकि इन अनुमानों से हमारी सरकार द्वारा हरियाणा की जनता के साथ किए गए वायदों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। (तालियां) यह विधि की एक विचित्र विडम्बना हैं कि गत वर्ष के विपरीत जिसमें इस शताब्दी का सबसे भंयकर सूखा पड़ा, चालू वर्ष में अभूतपूर्व भारी वर्षा हुई और राज्य के अधिकांश भागों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई। इस प्रकार प्रकृति ने हमें, हमारी सरकार के प्रथम दो वर्षों के कार्यकाल में मौसम की दो पराकाष्ठाएं दिखाई हैं। प्रत्येक प्राकृतिक आपदा ने राज्य

सरकार के समक्ष गम्भीर चुनौती रखी है और हमने इस चुनौती का सफलता पूर्वक सामना किया है, जैसा कि मैं बताऊंगा, और हमने विकास प्रक्रिया को छिन्न भिन्न होने से रोकने के अलावा जान माल की भी रक्षा की है। हताश आतंकवादियों के घृणित कार्यों से पानीपत, शाहबाद, पेहवा, कैथल तथा थानेसर आदि में निर्दोष नागरिकों की हत्या करने की कई एक घटनाएं हुई हैं। हमारी सरकार ने एक बार फिर इन घटनाओं की प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए अत्यधिक शक्ति तथा संकल्प का प्रदर्शन किया है और इन शर्मनाक घटनाओं के दोषी सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आतंकवादी हिंसा के सम्बन्ध में हमारे राज्य की संवेदनशील स्थिति के कारण हमारे राज्य पर विशेष जिम्मेदारी आ पड़ी है और इस लिए मुझे पुलिस बल तथा उसके शस्त्रागार को मजबूत करने के लिए फौरी तौर पर धन की व्यवस्था करनी पड़ी है। फिर भी, जहां गत वर्ष अभूतपूर्व सूखे के कारण राज्य की आय पूर्व वर्ष की तुलना में 2 2 प्रतिशत कम हुई है, इस वर्ष कृषि क्षेत्र में मानसून के अच्छे प्रभाव के कारण हमें 90 प्रतिशत वृद्धि की आशा है। राज्य की अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल दबाव पड़ने के बावजूद हमारी सरकार द्वारा लोगों के साथ किए गए वायदों को पूरा करने का हमारा उत्साह ठण्डा नही पड़ा है। हमने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरती है कि समाज के कमजोर और दलित वर्गों की सहायता करने के लिए नए प्रयत्न और विकासात्मक प्रक्रिया की गति को तेज करने में कोई कमी न आने पाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शुरू किए गए महत्वपूर्ण

उपायों में शिक्षित स्नातकों के लिए बेरोजगारी भत्ते की स्कीम की घोषणा तथा हमारे बुजुर्ग नागरिकों, विधवाओं तथा अपंगों को उदारशील वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा अन्य योजनाओं के लाभों को आगे बढ़ाना शामिल है।

नौवां वित्त आयोग

पिछले वित्त–वर्ष की विशेष घटना नौवें वित्त आयोग का फैसला है। सर्वप्रथम मुझे माननीय सदस्यों को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले वर्ष मई के महीने में हमारे साथ विस्तार–पूर्वक विचार–विमर्श करने के बाद, नौवें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने माननीय मुख्य मंत्री और हरियाणा सरकार को अपने विवेकशील और कुशल वित्तीय प्रबन्ध के लिए सार्वजनिक रूप से बधाई दी थी। हमारी जोरदार और प्रभावी पैरवी के कारण आयोग ने कानून और व्यवस्था की मशीनरी का आधुनिकीकरण करने के लिए 20 करोड़ रुपए तथा स्कूल–भवनों के निर्माण के लिए 4. 88 करोड़ रुपए विशेष रूप से आबंटित किए हैं। फिर भी कुल मिला कर 1989– 90 वित्त–वर्ष के लिए नौवें वित्त आयोग का फैसला कुछ अधिक उत्साहवर्द्धक नहीं रहा है। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञ है कि हमने इस वित्त आयोग के लिए विचारणीय विषयों का एक विकल्प प्रस्तावित किया था जिसमें इस देश के लोगों की आवश्यक ताओ और आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से परिलक्षित किया जा सके। देश में इन विचारणीय विषयों के बारे में गैर कांग्रेस (आई) शासित राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने मुख्य भूमिका

निभाई थी। किन्तु उनके प्रयासों से भी हरियाणा जैसे राजस्व–कुशल राज्य की कोई सहायता नहीं हुई। राज्यों तथा केन्द्र दोनों के लिए मानकित दृष्टिकोण के नीतिबद्ध प्रयोग का वर्ष 1989–90 के लिए सिफारिशों को करते समय सहारा नहीं लिया गया है। हरियाणा जैसे राज्यों के द्वारा राजस्व प्रयत्नों और वित्तीय अनुशासन को ध्यान में न रखते हुए अभी भी घाटे वाले और पिछड़े राज्यों को खैरात देने पर जोर दिया जाना जारी है।

आय कर तथा आबकारी शुल्कों के अन्तरण के लिए बनाए गए फार्मूले में गरीबी तथा पिछड़ेपन को अब अतिरिक्त महत्व दिया गया है, जिससे इन विभाज्य करों में हमारे प्रतिशत हिस्से में कमी आई है। दूसरी ओर, नौवें वित्त आयोग द्वारा घाटे को पूरा करने व सेवाओं के स्तर को बढ़ाने के लिये सिफारिश की गई लगभग 1,156 करोड़ रुपए की अनुदान–राशि में से भी हमें कोई हिस्सा नही मिलेगा। हमारे माननीय मुख्य मंत्री चौ० देवी लाल जी फिर भी राज्य के हितों के लिए एक जुझारू योद्धा की भूमिका निभाते रहैं हैं। उन्होंने 28 जनवरी, 1989 को कलकत्ता में हुए सम्मेलन और 9 तथा 10 फरवरी, 1989 को दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी राज्यों की संयुक्त भावनाओं को पूरे जोर शोर से व्यक्त किया है।

मुझे उम्मीद है कि नौंवा वित्त आयोग आठवीं योजना अवधि (1990– 95) के लिये अपनी दूसरी रिपोर्ट में हरियाणा के लिये अधिक उदार होगा।

आर्थिक सर्वेक्षण 1988– 89

''हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, 1988– 89, दस्तावेज जो माननीय सदस्यों को पहले ही दिया जा चुका है, गत वर्ष के दौरान आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। मैं इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं का जिक्र करना चाहूंगा। वर्ष 1987– 88 के दौरान राज्य अभूतपूर्व सूखे की स्थिति से गुजरा जिससे इसकी अर्थ–व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। तुरन्त अनुमानों के अनुसार राज्य की आय स्थिर कीमतों (1980– 81) पर 1986– 87 में 4,042 करोड़ रुपए के मुकाबले में 1987– 88 में 3,954 करोड़ रुपए हुई है, जिसमें 2.2 प्रतिशत की कमी दिखाई देती है, जबकि वर्तमान कीमतों पर यह 1986– 87 में 5, 931 करोड़ रुपए के मुकाबले में 198 7– 88 में 6,478 करोड़ रुपए हो गई है, जिस में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है। क्षेत्रवार विश्लेषण से यह पता चलता है कि प्राथमिक क्षेत्र का अंशदान 14.270 कम हुआ जबकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में क्रमशः 6.5 प्रतशित और 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सूखे का प्रभाव प्राथमिक क्षेत्र में बिल्कुल स्पष्ट है। वर्ष 1987– 88 में प्रति व्यक्ति आय (1980–81 की कीमतों पर) 2,572 रुपए थी जो गत वर्ष के स्तर के मुकाबले में 4. 4 कम हो गई है। वर्तमान कीमतों पर यह 1986– 87 के 3, 947 रुपए के मुकाबले में 4,214 रुपए हो गई थी। अभूतपूर्व सूखे के बावजूद हरियाणा में कीमतों में वृद्धि राष्ट्रीय औसत के मुकाबले में कम हुई है। जहां अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य

सूचकांक (आधार 1960 = 100) मार्च, 1987 में 686 से बढ़कर मार्च, 1988 में 753 हो गया जो 9.8 प्रतिशत वृद्धि दिखाता है तथा जो सितम्बर, 1988 में और बढ़ कर 806 हो गया, हरि– याणा का श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1972–73 = 100) मार्च, 1987 तथा मार्च, 1988 के बीच 288 से 313 तक बढ़ा और इसमें केवल 8.7 प्रतिशतकी वृद्धि हुई। वर्ष 1988– 89 के राज्य बजट अनुमानों के आर्थिक और कायत्मिक वर्गीकरण से पता चलता है कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण 139 करोड़ रुपए का था। जबकि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों मैं पूंजी निर्माण के लिए राज्य सरकार के 259 करोड़ रुपए का अशंदान इसके अतिरिक्त संशोधित वार्षिक योजना 1988– 89 चालू वर्ष 7वीं पंचवर्षीय योजना (1985– 90) का चौथा वर्ष है जिसके लिए 2,900 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया था। 1987– 88 तक राज्य योजना खर्च 1,371 करोड़ रुपए था और चालू वर्ष का परिव्यय 600 करोड़ रुपए नियत किया गया था। कुछ शीर्षो के अधीन योजना परिव्यय को बाद में 50 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया था। इस योजना के लिए धनराशि जुटाने के राज्य के साधनों में विभिन्न कारणों से कुछ कमी अनुभव की गई। विकास की स्कीमों के लिए उपलब्ध साधनों में कमी के मुख्य कारण अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किस्तें और केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पैंशन लाभों को देने के लिए लगभग 75 करोड़ रुपए का अप्रत्याशित खर्च तथा प्राकृतिक आपदाओं पर 12 करोड़ रुपए का खर्च है। कानून तथा व्यवस्था की मशीनरी को मजबूत

करने तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालय अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान प्रदान करने इत्यादि के लिए क्रमशः 7 करोड़ रुपये व 11 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई। 1988–89 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय को तदानुसार संशोधित करके 550. 63 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अन्य मदों के अलावा संशोधित परिव्ययों में बिजली के लिए 140 करोड़ रुपए, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए 96 करोड़ रुपए, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं के लिए 196 करोड़ रुपए, सहकारिता सहित कृ षि तथा सम्बद्ध सेवाओं के लिए 48 6 करोड़ रुपए और परिवहन तथा यातायात सुविधाओं के लिए 30.65 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

वार्षिक योजना 1989–90

बजट अनुमानों में राज्य वार्षिक योजना 1989– 90 के लिए 676 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिससे चालू वर्ष के पुनरीक्षित परिव्यय के०पर 23.36 प्रतिशत की वृद्धि प्रकट होती है। इसमें सहकारिता सहित कृषि तथा सम्बन्धित सेवाओं के लिए 62.88 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास के लिए 15.73 करोड़ रुपए, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण कायों के लिए 93.95 करोड़ रुपए, बिजली के लिए 202 करोड़ रुपए, उद्योगों के लिए 14 करोड़ रुपए, परिवहन तथा यातायात सुविधाओं के लिए 37.51 करोड़ रुपए, समाज सेवाओं के लिए 233.18 करोड़ रुपए, अन्य

सेवाओं के लिए 6.75 करोड़ रुपए तथा विकेन्द्रीकृत योजना के लिए 10 करोड़ रुपए शामिल हैं। सतलुज यमुना संपर्क नहर परियोजना के लिए परिव्यय 15 करोड़ रुपए नियत किया गया है। कृषि तथा उद्योगों के लिए हमारे आधारभूत ढांचे के विकास पर हमारी योजाना में अधिक बल दिया जाना जारी है। तदानुसार, हमने कुल योजना परिव्यय का 29.9 प्रतिशत बिजली क्षेत्र को तथा 13.9 प्रतिशत सिंचाई योजनाओं को आबंटित किया है। इसके अलावा, हमने मानव–संसाधनों के विकास के लिए तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र को कुल परिव्यय का 34.5 प्रतिशत आबंटित करके उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। अब मैं वर्ष 1989–90 में शुरू किए जाने वाले कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के सामने रखूंगा।

20 सूत्रीय कार्यक्रम

संशोधित 20 सूत्रीय कार्यक्रम का सर्वांगीण योजना कार्यकलापों के साथ समन्वय किया गया है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1988–89 में 73,332 परिवारों की सहायता करने के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 1989 तक 55,873 परिवारों को सहायता प्रदान की गई है जिनमें अनुसूचित जातियों के 29,013 परिवार शामिल हैं। 40 लाख श्रम दिवसों के रोजगार के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 1989 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 26.10 लाख श्रम दिवसों का रोजगार पैदा किया गया है जिसमें से 10.08 लाख

श्रम दिवसों का रोजगार अनुसूचित जातियों के परिवारों को दिलाया गया है। ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी 1989 तक 290 समस्याग्रस्त ग्रामों को 44० ग्रामों के लक्ष्य के विरुद्ध साफ पेय जल उपलब्ध कराया गया है जिससे कुल 3 85 लाख आबादी को लाभ हुआ है जिसमें 0.97 लाख अनुसूचित जातियों की आबादी शामिल है। व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 3.97 लाख के लक्ष्य के मुकाबले में 3.65 लाख बच्चे लाभान्वित किए गए हैं। आवास क्षेत्र में जनवरी 1989 तक इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 522 अनुसूचित जातियों के परिवारों को तथा कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत 284 परिवारों को आवासीय सुविधा दी गई है। गंदी बस्ती उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 8710 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है। जनवरी 1989 तक 19000 पम्पिंग सैटों के लक्षय के मुकाबले में 4947 पम्पिंग सैटों को बिजली दी गई है तथा 35480 उन्नत चूल्हैं लगाए गए हैं। वार्षिक योजना 1989–90 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकलापों पर ऐसे ही बल दिया जाता रहैंगा।

सिंचाई

सुनिश्चित सिंचाई की सुविधाओं ने देश में और विशेष तौर पर उत्तरीय राज्यों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बावजूद इसके कि हमारे पास सिंचाई के इतने अधिक बारहमासी स्त्रोत नहीं हैं, हमारा राज्य इस क्षेत्र में अनुकरणीय मापदण्ड स्थापित करता रहा

है। इस दिशा में लगातार प्रयत्नों के कारण हमारे राज्य में बावजूद भंयकर सूखे के वर्ष 1987–88 में कुल 66 प्रतिशत क्षेत्र सिंचाई के अधीन रहा है। विश्व बैक से सहायता प्राप्त नहर आधुनिकीकरण योजना ने अभी तक 45.9 करोड़ वर्ग फीट नहरों की लाइनिंग करने में सहायता की है जिससे 1920 क्यूसिक जल की मात्रा की बचत हुई है। (तालियां) 1988–89 के दौरान इस परियोजना का परिव्यय 31.50 करोड़ रुपए होगा। विश्व बैक के रिव्यू मिशन ने हरियाणा में इस परियोजना के अधीन निष्पादित कार्य के स्तर की सराहना की है। हमारा इरादा है कि हम जवाहर लाल नेहरू तथा लोहारू लिपट सिंचाई योजनाओं के लिए अगले वर्ष 5 करोड़ रुपए के परिव्यय से दक्षिणी–पश्चिमी हरियाणा के निर्जल तथाॅचे–नीचे भू–भागों को और हरा–भरा बनाएं। हथनी कुण्ड बैरेज का कार्य 1989– 90 के लिए 3 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ और प्रगति करेगा। भारत सरकार के विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अधीन 6.47 करोड की लागत से 10 नहरों की लाइनिंग का कार्य जून, 1989 तक पूरा हो जाएगा जिससे 6630 हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उत्पन्न होगी। अगले वर्ष इन सभी योजनाओं के अधीन 20,000 हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा करने का हमारा प्रस्ताव है। हमारी योजना की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने इंजिनीयरों को जल प्रबन्ध की आधुनिकतम तकनीकों तथा सिद्धान्तों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देना है।

सतलुज यमूना सम्पर्क नहर

मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार सतलुज यमुना सम्पर्क नहर के पंजाब के भाग को पूरा करने के महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपने हाथ पीछे खींच रही है। (शेम) हम इस मामले को केन्द्रीय सरकार के साथ लगातार उठा रहें हैं। इस दौरान परियोजना की लागत 1983 में 160 करोड़ रुपए से बढ़ कर 1988 में 430 करोड़ रुपए हो गई है। सम्भावित खाद्यान्न उत्पादन में भयंकर क्षति तथा इस परियोजना के पूरा न होने के कारण हमारे लोगों की आय में होने वाली क्षति निश्चित रूप से राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है। इस वर्ष इस परियोजना पर 34 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई हैं और अगले वर्ष और 15 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। मैं अपनी आशंका व्यक्त किये बिना नहीं रह सकता कि केन्द्रीय सरकार हरियाणा के साथ सम्भवतः इसलिए भेदभाव बरत रही है क्योंकि हमारा राज्य विरोधी पक्ष द्वारा शासित है। किन्तु मैं इस गरिमामय सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्यों का इस विषय में संयुक्त समर्थन प्राप्त होता रहा तो हम भारत सरकार से अपना उचित हक प्राप्त करने में सफल होंगे। (तालियां)

बाढ़ नियन्त्रण

हमारे राज्य की बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था को वर्ष 1988 की अभूतपूर्व बाढ़ के दौरान बहुत कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा है।

जुलाई से सितम्बर, 1988 तक होने वाली वर्षा सामान्य से कई गुना अधिक थी और फल स्वरूप यमुना, मारकण्डा, टांगरी, घग्गर तथा उनकी सहायक नदियां बाढ़ से उफन पड़ी और हमारे राज्य के काफी भाग को पानी में डुबो दिया। शुक्र है कि इस दिशा में किए गए अच्छे काम के कारण हमारे राज्य के 16 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को पहले ही बाढ़ से सुरक्षा प्रदान कर दी गई थी और इस प्रकार हमारी आधारभूत व्यवस्था तथा कृषि–उत्पादन को सम्भावित भारी नुकसान से बचाया जा सका। हां, इस प्रक्रिया में हमारी सरकार को बाढ–पीडित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए अपने साधनों से लगभग 12 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ा। वर्ष 1989–90 के लिए हमने बाढ सुरक्षा कार्यों के लिए 13 करोड़ रुपए की राशि रखी है और खारा, छुडानी तथा बहादुरगढ़ नालों पर चल रहा कार्य लगभग पूरा होने वाला है जिससे झज्जर तथा बहादुरगढ़ क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा।

बिजली

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त की हैं जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की अर्थ–वयवस्था के कृषि तथा उद्योग दोनों क्षेत्रों में अत्यधिक उत्साह दिखाई दे रहा है। बिजली में कटौती लगभग नहीं ही की गई और पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष के पहले 9 महीनों में 455. 5 करोड़ यूनिट की जगह हम 491.4 करोड़ यूनिट बिजली उपलब्ध करा सके हैं। (तालियां) वर्ष 1989

के अन्त तक पानीपत में 210 मैगावाट क्षमता का एक यूनिट तथा पश्चिमी यमुना नहर पन– बिजली परियोजना में 8–8 मैगावाट क्षमता के दो यूनिटों के चालू हो जाने से बिजली प्राप्ति की संभावनाएं निकट भविष्य में और भी उज्जवल हो जाएंगी। पानीपत में 210 मैगावाट क्षमता के एक और यूनिट को स्थापित करने के लिए प्रारम्भिक कार्य भी शुरू कर दिया गया है। बल्लभगढ़ में एक 216 मैगावाट क्षमता के गैस आधारित बिजली संयंत्र को तथा एच० बी० जे० गैस पर आधारित 600 मैगावाट क्षमता के एक और बिजली संयंत्र को लगाए जाने की स्कीम को भी हम भारत सरकार के साथ आगे बढ़ा रहैं हैं। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के लिए और अधिक पूंजीगत साधनों को जुटाने के उद्देश्य से बिजली वित्त निगम से परियोजनाओं के लिए पूंजी–ऋण देने के लिए सम्पर्क किया गया है। वर्ष 1989– 90 के दौरान बिजली के क्षेत्र में योजना परिव्यय 202 करोड रुपए का रखा गया है।

कृषि

हमारे राज्य के परिश्रमी किसान लगातार अपने राज्य को कृषि क्षेत्र में इस देश का एक अग्रणी राज्य होने का गौरव प्रदान किये हुये हैं। केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार में राज्य का अंशदान 5.42 प्रतिशत का है जबकि राज्य का कृषि–योग्य क्षेत्र केवल 1.96 प्रतिशत। तिलहन तथा दालों के उत्पादन पर हमने विशेष बल दिया हैं। कृषि में विविधता लाने हैंतु हमने फलों तथा सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बागवानी का एक अलग विभाग

कायम किया है। वर्ष 1989–90 के दौरान इस प्रयोजन के लिए 93. 55 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। हमारी कृषि अर्थव्यवस्था का उल्लेखनीय लोच इस तथ्य में परिलक्षित है कि जोरदार बाढ़ के बावजूद 24.10 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले में खरीफ 1988 के दौरान खाद्यान्नों की उपज 24.38 लाख टन रही है। वर्तमान रबी के भी आसार अच्छे हैं और हम रबी खाद्यानों में 60.40 लाख टन के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा रखते हैं। वर्ष 1989–90 के लिए हमने खाद्यानों का उत्पादन लक्ष्य 91.10 लाख टन निर्धारित किया है और गन्ना (गुड़), तिलहन तथा कपास के उत्पादन लक्ष्यों को क्रमशः 8.50 लाख टन, 3.85 लाख टन तथा 9. 50 लाख गांठें निश्चित किया है। अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत 2.05 लाख क्विटल प्रमाणित बीजों, 5.80 लाख टन रासायनिक खादों तथा 5000 मीट्रिक टन कीटनाशक दवाइयों की खपत से 28.58 लाख हैक्टेयर क्षेत्र आ जाने की आशा है। लघु सिंचाई सुविधाओं का विकास करने के लिए कम गहरे नलकूप लगाने तथा छिड़काव सिंचाई सैटों के लिए 1.02 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। 1989– 90 के दौरान 20,000 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं देने के लिए 12,000 और कम गहरे नलकूप तथा 2270 छिड़काव सिंचाई सैट लगाए जाएंगे।

अम्बाला जिले में कंडी क्षेत्र के विकास के लिए हम एक परियोजना तैयार कर रहैं हैं ताकि कल्लर और खारी भूमि का सुधार किया जा सके। इसके लिए धन विश्व बैक द्वारा जुटाया

जाएगा। हम जिप्सम खरीदने के लिए 1.75 करोड़ रुपए की तथा भूमि संरक्षण कार्यो के लिए 80 लाख रुपए की अनुदान राशि देंगे। अगले वर्ष 44 लाख रुपए की लागत से समेकित वाटर–शेड प्रबन्ध परियोजना जारी रखी जाएगी।

सहकारिता

11.00 बजे।

हमारी सहकारी ऋण संस्थाओं ने हमारी कर्जा माफी योजना को कामयाबी से पूरा करने में अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त की है। अभी तक, हरको बैक तथा राज्य भूमि विकास बैक ने 3.99 लाख व्यक्तियों को 33.61 करोड़ रुपए की ऋण–राहत दी है। (तालियां) इसके बावजूद हमने उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर नहीं होने दी है और परिणाम स्वरूप 1988– 89 के दौरान दीर्घ और मध्यम अवधि के 251 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए तथा 1988–90 के दौरान हमने 315 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। इसी प्रकार, अगले वर्ष के लिए हरियाणा राज्य भूमि विकास बैक का भूमि के विकास, बागवानी के विकास तथा कृषि संयतों के लिए 75 करोड़ रुपए के ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। हैफेड ने उर्वरकों के विपणन में मुख्य भूमिका निभाई है तथा इस वर्ष इसके द्वारा 65 करोड़ रुपए के उर्वरकों का विपणन किये जाने की संभावना है। राज्य की सहकारी चीनी मिलों ने 1987– 88 में 9.82 प्रतिशत की अभूतपूर्व वसूली दर प्राप्त की तथा 150.56 लाख क्विटल गन्ने की

पिराई की। इस वर्ष इन मिलों के द्वारा 180 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई किये जाने की संभावना है। हमने कैथल, महम और भूना में तीन नई सहकारी चीनी मिलों के लिए 1988– 89 के लिए 8.50 करोड़ रुपए और 1989– 90 के लिए 11.40 करोड़ रुपए की हिस्सा पूंजी की व्यवस्था की है। (तालियां) इस राशि के आधे की प्रतिपूर्ति एन० सी०डी० सी० द्वारा की जाएगी। 1989– 90 में सहकारिता के विकास के लिए 11.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। मुझे यह भी सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि चौधरी देवीलाल की सरकार ने गन्ने का मूल्य 35 रु० किवंटल दिया है जो सारे देश में सर्वाधिक है।

वन

वनीकरण में हमारी गतिशील नीति के कारण राज्य का कुल 9.3 प्रतिशत क्षेत्र शुरू के 3. 8 प्रतिशत के मुकाबले वनों के अन्तर्गत आ जाने की संभावना है। विश्व बैक से सहायता प्राप्त परियोजना के साथ–साथ व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण प्रयासों से अगले वर्ष 25.90 करोड़ रुपये के परिव्यय से 39,600 हैक्टेयर क्षेत्र और वनों के अतर्गत आने की संभावना है। उजड़ी हुई अरावली पर्वत्तमालाओं के पुनरुद्धार हैंतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिये हमने 4.13 करोड़ रुपये की एक योजना भेजी है। विभाग की वाणिज्यिक गतिविधियों जैसे क्रेट, सेबों के बक्से, फर्नीचर और कोयला आदि बनाने से 1989– 90 के दौरान 6.30 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

पशुपालन

राज्य के पशुधन में और अधिक सुधार लाने तथा उसे समृद्ध बनाने के हमारे प्रयास जारी हैं और आगामी वर्ष के दौरान 40 पशु चिकित्सालय तथा 1 पोलीक्लिनिक खोलने और 30 पशु चिकित्सालयों का दर्जा बढ़ा कर उन्हैं पूर्ण हस्पताल बनाने का प्रस्ताव है। हमारी सरकार मुर्गीपालन, सुअरपालन, भेड़पालन तथा बछड़ापालन करने के लिये पिछड़ी जातियों के सदस्यों को प्राथमिकता देती है और इस कार्य के लिए 1989–90 के लिए 2. 25 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त कमजोर वर्गों के 4500 परिवारों को भी अगले वर्ष इन व्यवसायों में सहायता प्रदान की जाएगी। विभाग का अगले वर्ष 598 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय से 31. 25 लाख टन दूध, 36.50 करोड़ अच्छे, 14 लाख किलोग्राम०न तथा 20 लाख ब्रॉएलर के उत्पादन का लक्ष्य है।

भस्म पालन

राज्य में मल्ल पालन को और विकसित करने के लिए हमारी योजना में आगामी वर्ष के लिए 1.85 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है। ऐसी आशा है कि 20,000 टन मछली पैदा करने के लिए 500 लाख मत्सय बीज स्टाक किए जाएंगे और इससे 4.50 लाख श्रम दिवस का रोजगार जुटाया जाएगा। वर्ष 1989– 90 के दौरान हिसार और कुरुक्षेत्र में मत्स्य किसान विकास अभिकरणों की स्थापना भी की जाएगी।

खाद्य तथा आपूर्ति

खाद्य तथा आपूर्ति विभाग ने केन्द्रीय पूल के लिए इस वर्ष जनवरी 1989 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि के 2.87 लाख टन के मुकाबले में 6 लाख टन से अधिक चावल खरीद किया है। आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानों का जाल ऐसी दुकानों की संख्या 6516 तक बढ़ जाने से और मजबूत कर दिया गया है और हमने ध्यान रखा है कि किसी भी उपभोक्ता को अपनी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई हासिल करने के लिए 2 किलो– मीटर से अधिक की दूरी तय न करनी पड़े। उपभोक्ताओं के हित की रक्षा हैंतु हमने हिसार और अम्बाला में दो जिला कष्ट–निवारण फोरम स्थापित करने का भी निर्णय किया है।

उद्योग

आर्थिक विकास के लिए हमारी सरकार की नीति औद्योगिकरण को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करती है। हमारी औद्योगिक नीति का लक्ष्य अपने राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए उदारतापूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करना है। जनेरेटिंग सैट सहायता अनुदान छोटे पैमाने के यूनिटों के लिए प्रति के०वी० ए० 1000 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपए और मध्य तथा बड़े पैमाने के यूनिटों के लिए प्रति के०वी०ए० 500 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है और सहायता अनुदान की अधिकतम सीमा भी बढ़ा कर 15 लाख रुपए कर दी गई है। केन्द्रीय/राज्य/मेवात

सहायता अनुदान भी 10 से 15 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। 1–4–88 के बाद स्थापित, विस्तारित या डाईवर्सीफाइ होने वाली यूनिटों को बिक्री कर की छूट या विलम्बन लेने का विकल्प दिया गया है। इलेक्ट्रानिक उद्योगों के लिए हमने और भी ज्यादा प्रोत्साहनों की घोषणा की है। बिजली प्राप्ति में सुधार के कारण इस प्रक्रिया को और बल मिला है। ऐसे ही 25000 और यूनिटों की स्थापना से आगामी वर्ष में छोटे औद्योगिक यूनिटों के फैलाव को अधिक मजबूत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 15 बड़े और मध्यम पैमाने के यूनिट भी स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम डबवाली, गोहाना तथा मूरथल में 3 नई औद्योगिक संपदाए स्थापित करके आवश्यक आधारभूत ढांचा खड़ा करने में बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसकी सहायता से बावल में एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड निर्माण संयंत्र और गुड़गाँव में एक रैक्स प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा वित्त निगम द्वारा सावधिक ऋणों के वितरण का लक्ष्य 1989–90 के दौरान 32 करोड़ रुपए होगा।

श्रम तथा रोजगार

सरकार ने औद्योगिक शांति बनाए रखने और कामगार श्रेणी के लिए उचित मजदूरी को सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए है। हमने 1– 1–89 से अकुशल कामगारों के लिए कम से कम मजदूरी 62.5/– प्रतिमास या औद्योगिक कामगारों के लिए 24 रु० प्रति– दिन और कृषक श्रमगारों के लिए 25 रुपए

प्रतिदिन कर दी है जो सम्भवत. देश मे सबसे अधिक है। (तालियां) आगामी वर्ष के दौरान दो और श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। मुझे यह बताते हुए अत्यधिक संतोष हैं कि हमारी सरकार ने 1 नवम्बर, 1988, हरियाणा दिवस के दिन से 100 रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगार स्नातकों को बेरोजगारी भत्ता देकर न केवल अपना चुनावी वचन निभाया है बल्कि एक अनुकरणीय प्रगतिशील कार्य किया है। (तालियां) इस योजना के लिए हमने अगले वर्ष 6.04 करोड़ रुपए की राशि निश्चित की है।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद् ने विकास के क्षेत्र में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सम्बन्धित नीति तथा उपायों पर सरकार को मूल्यवान मन्त्रणा दी है। अर्थ–व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक दूरस्थ संवेदनशील तकनीकी के प्रयोग के लिए हिसार में दो करोड़ रुपये की लागत से एक दूरस्थ संवेदनशील प्रयोगशाला केन्द्र की स्थापना की जा रही है। गुड़गांव में ग्वालपहाड़ी में सौर०र्जा केन्द्र की स्थापना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। टाटा०र्जा अनुसंधान संस्थान 10 करोड़ रुपये की लागत से ऐसी ही एक और परियोजना गुड़गांव में स्थापित करने जा रहा है। विभाग भी राज्य में 50– 50 किलोवाट क्षमता वाले दो सौर थर्मल पावर संबल तथा एक 20 किलोवाट क्षमता वाले सौर पी० वी० संयंत्र की स्थापना कर रहा है।०र्जा के गैर परम्परागत उपयोग

को 1989– 90 में समन्वित ग्रामीण०र्जा कार्यक्रम को तीन और खण्डों में विस्तारित कर के प्रोत्साहित किया जाएगा। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 1989–90 के लिए योजना परिव्यय 86 लाख रुपये रखा गया है।

तकनीकी शिक्षा

हमने व्यापक तथा सघन दोनों रूप से तकनीकी शिक्षा सुविधाओं को समृद्ध कर तकनीकी मानवशक्ति के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। जहां मुरथल में इंजीनियरिंग महाविद्यालय ने पहले ही कार्य करना शूरू कर दिया है और उस के लिए भवन निर्माण का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है, हिसार में एक और इंजीनियरिंग संस्थान स्थापित करने का हमारा प्रस्ताव है। नारनौल, उतावड, गुड़गांव तथा जीन्द में नए बहुतकनीकी संस्थान खोले जा रहैं हैं और महिलाओं के लिए फरीदाबाद में एक राजकीय बहुतकनीकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। (तालियां) तकनीकी शिक्षा के लिए योजना परिव्यय 6.15 करोड़ रुपए रखा गया है।

औद्योगिक प्रशिक्षण व व्यवसायिक शिक्षा

नई तकनीकी दक्षताओं को उत्पन्न व विकसित करने तथा शिक्षा को व्यवसायनिष्ठ बनाने पर जोर देना हमने जारी रखा है। विभाग ने औद्योगिक प्रशिक्षण सुविधाओं को उन्नत व विस्तृत करने के लिये वर्ष 1989–90 से वर्ष 1994– 95 तक लागू होने वाली 18 करोड़ रु० की एक परियोजना बनाई है। इसमें पचास

फीसदी तक सहायता लेने के लिये इस परियोजना को विश्व–बैक के सामने रखा जा रहा है। 1989–90 में महिलाओं के लिये दो और आई० टी० आई० तथा नये ट्रेड जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डाफ्टसमैन इत्यादि खोले जायेंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विकास के लिये अगले वर्ष का योजना परिव्यय 2.53 करोड़ रु० रखा गया है। व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 1989– 90 में सीटों की संख्या 8680 से बढ़ाकर 9720 कर दी जायेगी और एक राज्य स्तरीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाने की संभावना है। व्यवसायिक शिक्षा के लिये अगले वर्ष योजना परिव्यय 3.85 करोड़ रुपये है।

परिवहन

हरियाणा परिवहन अपने विस्तृत तथा कुशल परिवहन–जाल के माध्यम से परिवहन की मूल्यवान सेवा प्रदान कर रहा है। हमारी बसें प्रतिदिन 14 लाख यात्रियों को 9.7 लाख किलोमीटर की यात्रा कराती हैं। विभाग द्वारा अर्जित कामकाज के स्तर की हर मूल्यांकन में प्रशंसा हुई है तथा योजना आयोग ने पहले ही इस को सर्वोत्तम परिवहन उपक्रम के रूप में माना हुआ है। हमने मिनी बसों द्वारा ग्रामीण मार्गों पर सहायक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने का भी अद्वितीय कदम उठाया है और हमारा 61 बसों के वर्तमान बेड़े में 100 और मिनी बसों को जोड़ने का विचार है। इसके अतिरिक्त, टैम्पो तथा टैक्सियों के अनियमित परिवहन को रोकने तथा राज्य के लिए राजस्व अर्जित करने के

लिए ऐसे सभी वाहनों के पंजीकरण के लिए विस्तृत हिदायतें जारी की गई हैं और इस योजना को प्रभावकारी ढग से लागू करने के लिए एक सघन अभियान शुरू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 15 नवम्बर 1988 तक राज्य में 1,083 टैम्पो तथा टैक्सियों का पंजीकरण किया गया है जिस से सड़क कर तथा लाइसैसं फीस के रूप में 10.54 लाख रुपये की आय हुई है। 1989–90 की वार्षिक योजना में 200 नई बसों को खरीदने तथा 387 बसों को बदलने के लिए 15.10 करोड़ रुपए के परिव्यय का उपबन्ध किया गया है।

सबके तथा पुल

परिवहन के कुशल संचालन के लिए अच्छी सड्कों का होना एक अनिवार्य आवश्यकता है। अगले वर्ष की योजना का लक्ष्य वर्तमान सड्कों के 290 कि०मी० को सुधारना तथा 220 कि०मी० नई पक्की सड़कें जोड़ने का रखा गया है। जहाँ करनाल के पास यमुना पर एक दूसरे पुल का कार्य पहले ही हाथ में ले लिया गया है, हम फरीदाबाद के पास यमुना पर एक अतिरिक्त पुल तथा दूसरा पुल कुरुक्षेत्र–सहारनपुर सड़क पर बनाने की योजना बना रहैं हैं। मुरथल से करनाल तक 80 कि० मी० की दूरी में राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 1 को चार मार्गों वाला बनाने का कार्य काफी प्रगति पर है और उसके निर्धारित तिथि अर्थात् अप्रैल, 1991 से पहले पूरे हो जाने की सम्भावना है। 1988–90 के दौरान करनाल–अम्बाला–राजपुरा सड़क को भी चौड़ा किया जाएगा।

सड्कों तथा पुलों के विकास के लिए योजना परिव्यय 20 करोड़ रुपए रखा गया है।

ग्रामीण क्षेत्र की सड्कों के विकास के लिये अतिरिक्त साधन जुटाने की दृष्टि से हमने यह निर्णय लिया है कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड अधिक से अधिक ग्रामीण सम्पर्क सड्कों को उनके रख रखाव के लिये ले लेगा और अगले वर्ष से ऐसी नई सड्कों का निर्माण भी शुरू कर देगा। बोर्ड ने इस साल 400 करोड़ रुपए पहले ही लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें) को सड्कों के रख रखाव के लिये अदा कर दिये हैं और अगले वर्ष यह 8 करोड़ रुपये से भी ज्यादा लागत से 300 कि० मी० नई सम्पर्क सड्कों का निर्माण करेगा।

पर्यटन

हरियाणा में प्रदान की गई नई से नई पर्यटक सुविधायें देश में एक आदर्श स्थापित कर चुकी हैं। चौबीसी का चबूतरा (महम) में परम्परा व आधुनिकता का एक अनोखा सम्मिश्रण करके पर्यटक सुविधाओं का विकास करने की एक अद्वितीय योजना पर हम काम कर रहैं हैं। पिंजौर उद्यान में व आसाखेड़ा पर्यटक केन्द्र पर दो संगीतमय फव्वारे लगाये जा रहैं हैं और देश में पहली बार एक वातानुकूलित नौका की सुविधा अबूबशहर पर्यटक केन्द्र में दी गई है। सूरजकुंड में अब हर साल लगने वाला क्रापट मेला कल्पनाशील तरीके से संस्कृति व पर्यटन का एक साथ विकास

करने का एक उदाहरण है। सूरजकुंड में ही एक ओंडिटोरियम व रेस्तरां, फरीदाबाद में एक गोल्फ कोर्स और दमदमा व बहादुरगढ़ में नये पर्यटक केन्द्र तेजी से बन रहैं हैं। पानीपत, हिसार, सोनीपत व कर्ण–झील केन्द्रों पर पर्यटकों के लिये आवासीय सुविधा बढ़ाई जा रही है। विभाग की इन गतिविधियों को 1989–90 में 2.25 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय से चलाया जायेगा।

स्वास्थ्य सेवायें

'' 2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वास्थ्य'' के उद्देश्य के समवन में 15.29 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय से 161 उप केन्द्र, 61 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान आधारभूत ढांचे में और जोड़ दिए जाएंगे। अगले वर्ष कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत 2645 और कर्मचारियों को लाया जाएगा। 75 लाख रुपए का परिव्यय भारतीय चिकित्सा पद्धति की प्रोन्नति के लिए विशेष रूप से रखा गया है। हमने आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, रोहतक में तकनीकी मानव–शक्ति और सुविधाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता भी दी है। चालू वर्ष के दौरान हमने आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों को काफी अच्छा कर दिया है। रेडियो–चिकित्सा में एम० डी० डिप्लोमा, ऑर्थोडोन्टिक में एम० डी० एस० और प्रोसोथोडोन्टिक में एम० डी० एस० के नए पाठ्यक्रम चालू किए गये हैं और हृदय–विज्ञान (कार्डियोलोजी) और हृदय–शल्य चिकित्सा (कार्डिएक

सर्जरी) के नए विभाग बनाए गए हैं। इस वर्ष कैंसर–अस्पताल को भी पूरा किया गया है। आगामी वर्ष के दौरान 15 करोड़ रुपए की लागत वाला एक बॉडी कैट स्कैन संयत्र चालू कर दिया जाएगा और दन्त–स्वास्थ्य विज्ञान में डिप्लोमा भी चालू किया जाएगा। अधोस्त्रातक पाठ्यक्रमों के लिए 50 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाले एक नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की अग्रोहा में मंजूरी भी दी गई है। जनता की सेवा में राज्य सरकार और एक समाजसेवी समुदाय के बीच सहयोग का यह एक ठोस उदाहरण होगा। 1989–90 के लिए आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए योजना परिव्यय 19.08 करोड़ रुपए है।

जन–स्वास्थय

हमारा राज्य अधिकाधिक गांवों को नलों द्वारा पीने का पानी उपलब्ध कराने की सुविधा देने के लिये अग्रणी रहा था। सातवी योजना अवधि के दौरान इस सुविधा के अन्तर्गत लाए जाने वाले 2000 चुने गए समस्याग्रस्त गांवों में से, जनवरी 1989 तक ऐसी सुविधाएं 1740 गांवों को दे दी गई हैं। 1989–90 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित परिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत 5.50 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त 25.88 करोड़ रुपयों का योजना परिव्यय 400 और समस्याग्रस्त गांवों को जल प्रदाय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रखा जा रहा है।

शिक्षा

हम इस तथ्य से पूर्णतः परिचित हैं कि हरियाणा में साक्षरता दर बहुत कम हैं। इसलिए हमने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक जोर दिया है और इस उद्देश्य के तहत हम ने प्राथमिक शिक्षा का एक अलग निदेशालय स्थापित किया है। मुझे विश्वास है कि विकास के इस महत्वपूर्ण पहलू को अब वांछित बढ़ावा मिलेगा। इस वर्ष के दौरान बालिकाओं के लिए 200 प्राथमिक विद्यालय खोलने तथा 112 विद्यालयों के लिए अतिरिक्त अध्यापकों तथा सभी साजसामान की व्यवस्था करने की भी योजना है। अगले वर्ष 100 और प्राथमिक विद्यालयों, 60 माध्यमिक विद्यालयों और 25 उच्च विद्यालयों का दर्जा बढ़ा दिया जाएगा। इस वर्ष हमने प्रति विद्यार्थी प्रति विद्यालय–दिन की दर से 1/– रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि दे कर खानाबदोश जातियों के बच्चों को विद्यालय जाने के लिए आकर्षित करने हैंतु एक अद्वितीय योजना की घोषणा की है। (तालियां) इस योजना को अगले वर्ष भी जारी रखा जाएगा। शैक्षणिक योग्यताओं को सुधारने के लिए, 8 जिला स्तरीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान खोले जा रहैं हैं, और बाकी के 4 जिलों में यह अगले वर्ष खोले जाएंगे। अगले वर्ष के दौरान बाकी के तीन जिलों में भी एक–एक नवोदय विद्यालय खोला जायेगा।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा विश्वास है कि एक सन्तुष्ट अध्यापक समुदाय ही शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राज्य की

सहायता कर सकता है। सरकार ने और बातों के अलावा विश्वविद्यलय तथा महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन मानों के आधार पर संशोधित किया है, जिससे राज्य पर 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है। उच्चतर अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय परिषद् स्थापित की गई है और शिक्षा की राष्ट्रीय नीति को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए एक दूसरी परिषद् का गठन किया जाने वाला है। अगले वर्ष तावडू तथा मण्डी डबवाली में दो सरकारी महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है और हमारा राज्य में एक खुला विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। खेल–कूद हमारे राज्य ने कई विलक्षण खेल प्रतिभायें दी हैं जिन्होंने अपने राज्य व देश के लिये सम्मान अर्जित किया है। खेल प्रतिभाओं को और अधिक विकसित करने की दृष्टि से कुछ चुने हुये खेलों जैसे कुश्ती व जिमनास्टिक में हमने खेलकूद नर्सरियां बनाई हैं जिनमें हमारे खिलाड़ी परम्परागत रूप से दक्ष रहैं हैं। जिमनास्टिक की दो नर्सरियां अम्बाला व यमूनानगर में तथा कुश्ती की एक नर्सरी रोहतक में स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य कई खेल गतिविधियों के विकास के लिये अगले वर्ष 1.75 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

समाज कल्याण

सामुदायिक लाभ के लिए समाज–कल्याण योजनाओं को हम निरन्तर वित्तीय तथा प्रशासनिक सहारा दे रहैं हैं। हमारी

वृद्धावस्था पेन्शन योजना से हमारे वरिष्ठ नागरिकों में गर्व, आत्म–सम्मान तथा मान्यता की एक नई तथा अद्वितीय भावना आई है और इसने देशभर में चेतना पैदा कर दी है। इस वर्ष 7.82 लाख व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन दी गई और 79.60 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई तथा आगामी वर्ष इस योजना के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान है। (तालियां) विधवा पेन्शन भी 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपये प्रतिमास कर दी गई है। हमने किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को लागू किया है और तदानुसार हमने 5 पर्यवेक्षण गृहों के अतिरिक्त प्रत्येक जिले में किशोर कल्याण बोर्डों. अम्बाला, भिवानी तथा सोनीपत में 3 किशोर न्यायालय, तथा मधुबन, भिवानी और छछरौली में 3 किशोर गृह स्थापित किए हैं। इस क्षेत्र को दिया गया महत्व इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि हमने इस विभाग के लिए 97.92 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा है। अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा अन्य दलित वर्गों की सामाजिक–आर्थिक उन्नति के लिए हरिजन बस्तियों के पर्यावरण सम्बन्धी सुधार, आवासीय सहायता, पेय जल प्रदाय तथा हरिजन चौपालों आदि की योजनायें चलाई जा रही हैं। इन वर्गों के विद्यार्थियों की, छात्रवृत्ति राशि भी कक्षा 6 से 8 वीं के लिए 15 रुपये से बढ़ा कर 30 रुपए प्रतिमास तथा कक्षा 9 वीं से 11 वीं के लिये 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपए प्रतिमास कर दी गई है और लेखन सामग्री अनुदान भी मिडिल स्कूल कक्षाओं के लिए 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये वार्षिक तथा उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए 20 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया

गया है। 1989–90 के दौरान राज्य सरकार हरियाणा हरिजन कल्याण निगम तथा हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम को अपनी हिस्सा पूजी के रूप में क्रमशः 50 लाख रुपए तथा 60 लाख रुपए और देगी।

विशेष संघटक योजना

हमारी सरकार ने अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये हमेशा खास रुचि दिखाई है। अनुसूचित जातियों के परिवारों की सहायता केलिये इस वर्ष 54.40 करोड़ रुपए व अगले वर्ष 70. 86 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जनवरी 1989 तक 29,013 परिवारों की सहायता की गई है और अगले वर्ष 41,713 परिवारों की सहायता का लक्ष्य है।

मेवात विकास बोर्ड

मेवात विकास बोर्ड के लगातार विकास प्रयत्नों से दक्षिणी हरियाणा का यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। रोजका मेव में विकसित होता हुआ औद्योगिक क्षेत्र मेवात के बदलते हुये स्वरूप का एक ठोस उदाहरण है। बोर्ड की गतिविधियों के लिये अगले वर्ष योजना परिव्यय 3 करोड़ रुपए रखा गया है। (तालियां) इसके अतिरिकत मोरनी हिल्ज के पिछड़े पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिये सरकार ने मोरनी हिल्ज डिवैल्पमैंट बोर्ड का भी गठन किया है।

मैचिंग ग्रांट योजना

हमारे माननीय मुख्य मन्त्री मैचिंग ग्रांट योजना के अग्रणी रहैं हैं। उनके मार्ग दर्शन में विकास की समस्त गतिविधियों में हमने जनता को शामिल किया है और हमारा '' जन शक्ति '' में पूर्ण विश्वास है। इस आदर्श के साथ हमारी सरकार ने जनहित के अधिकाधिक कार्य पंचायतों और लोगों के सहयोग से करने को पू रा बढ़ावा दिया हैं और इसके परिणाम अत्यन्त संतोष– जनक रहैं हैं। राजकोष से हमने उदारतापूर्वक मैचिंग ग्रांट प्रदान की है और इस वर्ष तथा अगले वर्ष इस मद में क्रमशः 2.66 करोड़ रुपए तथा 3.32 करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है। माननीय मुख्य मन्त्री जी अपने राहत कोष से भी बजट के बाहर मैचिंग ग्रांट दे ते रहैं हैं। चालू वर्ष में पूरे राज्य में अनेक विकास कार्यों के लिये उन्होंने 1.12 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं। (तालियां) हमने यह महसूस किया कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं हैं। उनके साधनो को बढ़ाने के लिये सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रो में बिकने वाली दे शी शराब की प्रत्येक बोतल पर 1 रुपए की दर से अतिरिक्त आबकारी कर लगने का फैसला किया है। यह निर्णय किया गया है कि इस कर से प्राप्त होने वाली आय पचा यत समितियों व पंचायतों के मध्य निम्न प्रकार से बांटी जायेगीः –

(1) पंचायतों के क्षेत्र में आने वाले ठेकों पर बिक्री की माता के अनुसार 25 प्रतिशत हिस्सा पंचायतों को दिया जायेगा।

(2) 50 प्रतिशत हिस्सा पंचायत समितियों के क्षेत्र में पड़ने वाली पंचायतों को उनकी नवीनतम जनगणना के अनुसार दिया जायेगा।

(3) 25 प्रतिशत हिस्सा पंचायत समिति द्वारा अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने के लये रख लिया जायेगा।

इसी आधार पर नगरपालिका क्षेत्रों में शहरी ठेकों से बकने वाली देशी शराब पर चुंगी की जगह लगाये गये अतिरिक्त आबकारी कर से आने वाला राजस्व सम्बन्धित नगरपालिका को दिया जायेगा।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें

राज्य के योजना परिव्ययों के अलावा, जिनका जिक्र मैंने अभी किया है, 1989–90 के बजट अनुमानों में केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय योजनाओं तथा अन्य विकास योजनाओं के लिये योजना स्तर पर 98 44 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

प्राकृतिक आपदायें

गत वर्ष के बिल्कुल विपरीत समाप्त होने वाला वर्ष मानसून वर्षा के कारण भारी जल–प्रलय का वर्ष था जिसमें पिछले कई सालों का वर्षा का रिकार्ड टूट गया। बाबू द्वारा सड़कों, सिंचाई कार्यों तथा मकानों इत्यादि को व्यापक क्षति पहुंची थी।

यद्धपि मानव जीवन हानि को लगभग पूर्ण रूप से रोक लिया गया फिर भी बहुत से व्यक्ति बेघर–बार हो गये। माननीय सदस्य हमारी 192.10 करोड रुपए की मांग के विरुद्ध बाढ़ राहत के लिए 32.14 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने में भारत सरकार की ''दरियादिली'' से अवगत हैं। इस तुच्छ केन्द्रीय सहायता ने स्पष्ट रूप से हमारी सीमित साधन स्थिति को नहीं सुधारा, फिर भी हमने भारत सरकार द्वारा दिए गए धन के अतिरिक्त प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत पर 12 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। मैंने पहले भी कहा है कि इस अप्रत्याशित खर्च के कारण राज्य पर भारी वित्तीय दबाव पड़ा है। खर्च की बड़ी–बड़ी मदें कृषि सहायता अनुदान के लिये 4.12 करोड़ रुपए, भोजन तथा आश्रय के लिए 3. 75 करोड़ रुपए, सड्कों की मरम्मत के लिए 5.50 करोड़ रुपये सिंचाई संकर्मों की मरम्मत तथा पानी की निकासी के लिए 14.20 करोड़ रुपए तथा क्षतिग्रस्त ट्रांसफारमरों की मरम्मत के लिए 2.60 करोड़ रुपए थीं। मुख्य मन्त्री के राहत कोष से भी इस प्रयोजना के लिए 1.42 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी।

संसाधन संग्रह

हमारी सरकार को इस बात का पूरा एहसास है कि इसकी महत्वाकांक्षी कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं को केवल एक सुदृढ़ साधन आधार के द्वारा ही कार्य रूप दिया जा सकता है। नए साधनों को तलाशने की दृष्टि से 1987 में एक समिति गठित की गई थी। संसाधन समिति अपना बहुमूल्य परामर्श

देती रही है जिसके परिणाम स्वरूप हम राज्य की जनता पर किसी प्रकार का बोझ बढ़ाए बिना विद्यमान राजस्व तथा पूंजीगत ढांचे को विवेकसंगत और प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग में लाने में समर्थ रहैं हैं। विशेष रूप से, उपयोग में न लाई गई और फालतू पड़ी सरकारी जमीनों के बड़े भू–भाग हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जरिए आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग में लाए जा रहैं हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को 2.5 करोड़ रुपए तक की प्रारम्भिक प्राप्ति हुई है जिसके आगामी वर्ष में कई गुना हो जाने की संभावना है। इसी प्रकार निष्कात सम्पत्तियों के कब्जों के विनियमन से चालू वर्ष के दौरान 3.17 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है और भविष्य मैं होने वाली वसूलियां चरणबद्ध ढंग से 10 करोड़ रुपए से भी अधिक होने का अनूमान है। बिजली की दरों में संशोधन से, जिससे बिजली उत्पादन की बढ़ी हुई लागत का केवल एक छोटा सा भाग ही पूरा होगा, चालू वर्ष में 60.65 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। समिति के परामर्श पर उठाया गया एक आवश्यक कदम अचल सम्पत्ति के कम मूल्यांकन की प्रथा को समाप्त करना था जिससे सरकार को स्टाम्प शुल्क के रूप में भारी राजस्व की हानि हो रही थी। जिला तथा उप–जिला स्तरों पर मूल्यांकन समितियों के गठन के कारण इस वर्ष स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन फीसों द्वारा अनुमानतः 13 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व वसूल किया जाएगा। अतः मैं अनुभव करता हूं कि संसाधन समिति के बहुमूल्य मार्गदर्शन में अपनी स्कीमों के

लिये वित्त जुटाने की मेरी चिन्ता निरन्तर कम होती जाएगी जैसे जैसे हम अपने प्रयासों में आगे की ओर बढ़ेंगे।

संशोधित, अनुमान 1988–89

वर्ष 1988–89 के लिये संशोधित अनुमान, चालू वर्ष के लिये बजट अनुमानों को प्रस्तुत करने के बाद के हालातों को ध्यान में रखते हुए यह दर्शाते हैं कि यह वित्त वर्ष बजट अनुमानों में दिखाए गए 236.32 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले में भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों के अनुसार 19. 8 करोड़ रुपए के घाटे के साथ समाप्त होगा। (तालियां) ये आकड़े हमारी सरकार की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के होते हुए भी कुशल वित्त प्रबन्ध प्रणाली को बनाए रखने के हमारे इरादे को दर्शाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस वर्ष राज्य वित्त पर कई कारणों से प्रतिकूल दबाब पड़े हैं। इसके अति– रिक्त कुछ प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिये कुछ अतिरिक्त योजना परिव्यय स्वीकृत किए गए थे और राज्य योजना परिव्यय में कांट–छांट की गई ताकि यह राज्य सरकार के दायित्वों को देखते हुए परिवर्तित आवश्यकताओं तथा साधनों के अनुरूप हो जाए। फलस्वरूप संशोधित राज्य योजना परिव्यय 600 करोड रुपए के मूल परिव्यय के मुकाबले में 550.63 करोड़ रुपए रखा गया है।

वर्ष 1988–89 के लिये अथशेष (–) 3.06 करोड़ रुपए के अनुमानित अथशेष के मुकाबले में (–) 7.51 करोड़ रुपए आया

है। (–) 7.51 करोड़ रुपए के अथशेष में 31 मार्च, 1988 को राज्य सरकार द्वारा धारित 16.85 करोड़ रुपए के खजाना बिलों को समायोजित किया गया है। वर्ष के दौरान राजकोष पर अतिरिक्त भार अभूतपूर्व बाढ़ आने से राहत, मरम्मत तथा पुनर्वास के कार्यों (12 करोड़ रुपए), पेंशनों तथा सेवांत लाभों के संशोधन और महंगाई भत्ते की किस्तें देने (74.76 करोड़ रुपये), वृद्धावस्था पेंशन और बेरोजगारी भत्ता जैसे सामजिक सुरक्षा उपायों, (13 करोड़ रुपए), महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षकों आदि के वेतनमानों के संशोधन इत्यादि (11 करोड़ रुपए) और आतंकवादियों की बढ़ी हुई गतिविधियों के कारण कानून और व्यवस्था के प्रबंधों को मजबूत करने (7 करोड़ रुपए) के कारण रहा है।

इस वर्ष के योजना परिव्ययों को पुनर्व्यवस्थित करते समय हमने इस बात का ध्यान रखा है कि धन की कमी के कारण बिजली व सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विकास के क्षेत्रों तथा अन्य लोकु संकर्मों को कोई बाधा न आये। विकास कार्यों के लिये अधिकाधिक साधन जूटाने का हमारा संकल्प इस बात से जाहिर है कि वर्ष 1988–89 के दौरान अल्प बचत संग्रह में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस साधन का सफलतापूर्वक दोहन करने से हमारी सरकार बजट में व्यवस्थित 110 करोड़ रुपयों के ऋण के विरुद्ध भारत सरकार से 170 करोड़ रुपयों का ऋण, ले सकी हैं। आने वाले साल में भी हम इस गति को बनाये रखने की आशा करते

है। दूसरी ओर, पहले के वर्षों में शुरू किए गए सरकारी खर्च में किफायत लाने के उपायों को जारी रखा जाएगा तथा वाहनों, फर्नीचर कीमती वस्तुओं और अनुत्पादक चीजों पर किए जाने वाले खर्च को यथा सम्भव सीमित रखा जाएगा। उपरिवर्णित परिस्थिति के बावजूद तथा राज्य को रोजमर्रा की रोकड़ सहायता दिए जाने में भारतीय रिजर्व बैक की प्रतिबन्धात्मक नीति के बावजूद मैं संतोषपूर्ण ढंग से कह सकता हूं कि राज्य की अर्थोपाय स्थिति को सारे वर्ष पूर्ण नियन्त्रण में रखा गया है। (तालियां)

बजट अनुमान तथा वार्षिक योजना 1989–90

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 1989– 90 के लिए०पर बताए गये योजना परिव्यय तथा गैर योजना व्यय को सम्मिलित करने वाली बजट प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उभरने वाली राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करता हूं–

(रुपए करोडों मे)

संघटक	संशोधित अनुमान 1987– 88		लेखे 1987–88	बजट अनुमान 1988–89	संशोधित अनुमान 1988– 89	बजट अनुमान 1989–90
1	2		3	4	5	6

1.	अथ शेष					
(क)	महालेखाकार के अनुसार	(-)43.57	(-)43.57	(-)44.26	(-)29.75	(-)42.02
(ख)	भारतीय रिजर्व बैक के अनुसार	(-)2.37	(-)2.37	(-)3.06	(-)7.51	(-)19.78
(ग)	प्रतिभूतियों में निवेश	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98
2.	राजस्व लेखा					
	प्राप्तियां	1357.98	1303.84	1447.47	1458.85	1665.52
	खर्च	1314.39	1287.48	1349.99	1512.76	1623.35
	अधिशेष (+) / घाटा (–)	(+)43.59	0116.36	(+)97.48	(-)53.91	(+)42.17
3.	पूंजीगत खर्च	140.23	60.49	132.58	132.12	126.89
4.	सार्वजनिक ऋण					
	लिया गया	586.98	542.07	532.94	409.65	610.28

	ऋण					
	भुगतान	462.30	443.09	411.66	216.67	416.51
	निवल	(+)124.68	(+)98.98	(+)121.28	(+)192.98	(+)193.77
5.	कर्जे और पेशगिया					
	पेशगियां	177.63	198.26	221.91	188.28	241.80
	वसूलियां	28.37	25.35	33.91	26.50	32.82
	निवल	(-)149.26	(-)172.91	(-)188.00	(-)161.78	(-)208.98
6.	अन्तर्राज्यीय निपटान					
7.	आकस्मिकता निधि में विनियोजन					
8.	आकस्मिकता निधि निवल		(+)2.89			
9.	छोटी बचतें, भविष्य निधि	(+)96.94	(+)87.60	(+)48.38	(+)86.74	(+)53.27

	आदि निवल					
10.	जमा तथा पेशगिया– आरक्षित निधियां, निलम्बित तथा विविध निवल	(+)23.59	(+)43.00	(+)20.18	(-055.82	(+)30.20
11.	प्रेषण (निवल)		(-)1.61			
12.	वर्ष का इति शेष					
(क)	(1)महालेखा कार के अनुसार	(-)44.26	(-)29.75	(-)77.52	(-)42.02	(-)58.48
	(2)भारतीय रिजर्ब बैक के अनुसार	(-)3.06	(-)7.51*	(-)36.32	(-)19.78	(-)36.24
(ख)	प्रतिभूतियो	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98

	में निवेश					

*भारतीय रिजर्व बैक द्वारा सूचित 31 मार्च 1988 को बकाया 16.85 करोड़ रुपए के खजाना बिलों के समायोजन के पश्चात।

उपर्युक्त विवरण से यह पता चलता है कि भारतीय रिजर्व बैक की बहियों के अनुसार वर्ष 1989– 90 के अन्त में 36. 24 करोड़ रुपए का घाटा होने की संभावना है जबकि प्रारंभिक घाटा 19.78 करोड़ रुपए का था। राजस्व लेखे से 42.17 करोड़ रुपये का अधिशेष होने की संभावना है तथा शुद्ध सार्वजनिक ऋण 193.77 करोड़ रुपये की सीमा तक होगा। कर तथा गैर–कर दोनों राजस्व प्राप्तियों के बारे में अनुमान है कि वे नौवें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित दर से कुछ अधिक दर पर ही बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर, राज्य आबकारी शुल्क से राजस्व 1988–89 से 17 प्रतिशत से अधिक बढ़ने वाला दिखाया गया है तथा आगामी वित्त वर्ष के लिए आबकारी नीति में हाल ही में किये गये परिवर्तनों के परिणामस्वरूप यह वृद्धि और भी अधिक हो सकती है। इसी प्रकार, बिक्री कर से राजस्व जिसके 14.8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, कर चोरी रोकने के उपायों के परिणामस्वरूप तथा केन्द्रीय सरकार के वायदे के मुताबिक अगले वर्ष के मध्य तक लगाये जाने वाले प्रेषण कर से संभव प्राप्तियों के कारण और बढ़ जाने की संभावना है। गैर–योजना प्रयोजनों के लिए व्यय और आय का अनुमान लगाने में भी, नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों

को ध्यान में रखा गया है। वर्ष के दौरान कानून और व्यवस्था की मशीनरी को मजबूत बनाने के लिये 20 करोड़ रुपए के अनुदान तथा स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिये 4.88 करोड़ रुपए के अनुदान जिनकी नौवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है, को शामिल कर लिया यया है। आगे मंजूर की जाने वाली मंहगाई भत्ते की किस्तों के भुगतान के लिये कोई उपबंध नहीं किया गया है। केन्द्र प्रायोजित स्कीमों और अन्य विकास स्कीमों के लिए 98.44 करोड़ रुपए के परिव्यय के अलावा 1989–90 के बजट अनुमानों में राज्य योजना परिव्यय के लिए 676 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है। सिंचाई और बिजली क्षेत्रों के लिए कुल 290.95 करोड़ रुपए के परिव्यय से जो चालू वर्ष के पुन– रीक्षित परिव्यय से 25.39 प्रतिशत अधिक है, हमारे राज्य में कृषि और उद्योग के विकास को दी गई उच्चतम प्राथमिकता प्रकट होती है। इसके अतिरिक्त 1969–90 के लिए कृषि और ग्रामीण विकास के लिए परिव्यय से वर्तमान वर्ष के परिव्ययों पर 20.38 प्रतिशत की वृद्धि तथा सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के लिए 19.37 प्रतिशत की वृद्धि दी गई है। मैं कोई नया कर या शुल्क लगाने का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं, (तालियां) न ही मैं किसी वर्तमान कर की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहा हूं। (तालियां) परन्तु, इस तथ्य के बावजूद माननीय सदस्य सराहना करेंगे कि 1989–90 के लिए 36. 24 करोड़ रुपए के घाटे को बिल्कुल सुरक्षित तथा प्रबंधनीय सीमाओं के भीतर रखा गया है। परन्तु साथ ही साथ मुझे यह भी चिन्ता है कि केन्द्र के मेरे साथी केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने केन्दीय

बजट में और बजट–पूर्व उपायों के द्वारा रेल–भाड़े में वृद्धि, कोयले और स्टील के सरकारी मूल्यों में वृद्धि, और विभिन्न वस्तुओं पर आबकारी शुल्क में वृद्धि करके भारी बोझ डाला है। इन उपायों से राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से बहुत अधिक मूल्य–वृद्धि होगी जिससे हमारे राज्य के नागरिकों पर भी निश्चित रूप से वित्तीय, बोझ पड़ेगा। इसलिए मैं सोचता हू कि राज्य का एक कर मुक्त बजट प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी जनता को उनकी परेशानियों को और न बढ़ा कर केवल सीमित राहत ही दे रहा हूं। (तालियां) राज्य सरकार को भी परिवहन तथा बिजली सेवाओं के प्रबंध में निपुणता और सुधार लाना होगा ताकि मूल्य वृद्धि के बुरे प्रभावों को सीमित रखा जा सके। मुझे फिर भी विश्वास है कि कुशल वित्तीय प्रबंध और बचत के उपायों के कारण वर्ष 1989–90 का 36.24 करोड़ रुपए का छोड़ा हुआ घाटा और कम हो जाएगा। मुझे यह भी विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार आगामी वर्ष के मध्य तक प्रेषण कर लगाने के अपने वचन को निभाएगी। इस उपाय से लगभग 50.00 करोड़ रुपए वार्षिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

सरकारी कर्मचारियों को सुविधायें

हमारा विश्वास है कि सरकारी योजनाओं को पूर्णतया प्रभावकारी ढंग से लागू करने की दृष्टि से सरकारी कर्मचारियों का हौंसला, जो इन योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं ंचा रखा जाना चाहिये और हमने इस विश्वास को ध्यान में रखते हुए अपने

कर्मचारियों को अप्रत्याशित लाभ प्रदान किए कैंप। पहली बार हमारी सरकार ने भारत सरकार की ही तरह उन कर्मचारियों को वर्ष 1987– 88 के लिये 27 दिन के वेतन के बराबर बोनस स्वीकृत किया है (तालियां) जो किसी उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस स्कीम या किसी अन्य अनुग्रह स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते। इससे 22.22 करोड रुपए का वित्तीय बोझ आयेगा। परन्तु बाढ़ इत्यादि के कारण सरकार की कठिन अर्थोपाय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोनस का भुगतान कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा करके किया जायेगा। हमने इसके अतिरिक्त चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 1986 से संशोधित पेन्शन तथा सेवान्त लाभ देने के अपने निश्चय को भी कार्यरूप दिया है, जिसके कारण होने वाले खर्च का अनुमान चालू वर्ष में 19.32 करोड़ रुपये कर अगले वर्ष में 7.50 करोड़ रुपए का है।

हमने कर्मचारी संगठनों की विभिन्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण लेने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त मंत्रियों की समिति भी गठित की है। इसकी सिफारिशों के आधार पर हमने दौरे पर जाने वाले कर्मचारियों को देय दैनिक भत्ते की दरों में संशोधन किया है और चिकित्सा भत्ता भी 200 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 360 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है। (तालियां) यह राज्य सरकार के समक्ष आई अत्याधिक वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद कर्मचारियों की वास्तविक कठिनाइयों के

लिए जब वे दौरे पर हों या जब उन्हैं चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो, क्षतिपूर्ति करने के लिए किया गया है। विश्वविद्यालय के शिक्षको तथा गैर–सरकारी तथा सरकारी महाविद्यालयो के शिक्षकों के वेतनमान भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आधार पर संशोधित किए गए हैं। आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, रोहतक के अध्यापकों के वेतनमान भी चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर संशोधित कर दिए गए हैं। वेतन विसंगति आयोग ने अपनी रिपोर्ट 27– 2– 89 को प्रस्तुत कर दी है। हम पूरी तेजी से इसकी सिफारिशों की जांच करेंगे और उन्हैं कार्य रूप देंगे। हमारी सरकार ने इन कर्मचारी कल्याण उपायों को इस प्रत्यक्ष विश्वास के साथ किया है कि सरकार का उनके प्रति सकारात्मक तथा उदार दृष्टिकोण उनको और प्रेरित करेगा कि वे हमारे राज्य के निर्माण के लिए प्रयासों में अपना सर्वोत्तम योगदान दें। अपने भाषण को समाप्त करने से पूर्व मैं कर्मचारियों की उस टीम के प्रति अपना आभार और धन्यवाद अवश्य व्यक्त करुंगा जिन्होंने इन बजट अनुमानों को सावधानीपूर्वक तैयार करने में कठिन परिश्रम किया है। महालेखाकार, हरियाणा ने इसमें विशेषतौर से हमारी सहायता की है। वित्त विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने वास्तव में बजट अनुमानों को समय पर तैयार करने, संकलित तथा प्रस्तुत करने में कठिन परिश्रम किया है। संघ राज्य क्षेत्र के मुद्रणालय का तथा हरियाणा मुद्रणालय का इस कार्य के निष्पादन में सदैव की भांति अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

महोदय, अब मैं इस सदन के विचार तथा अनुमोदन के लिए इन बजट अनुमानों को प्रस्तुत करता हूं। जय हिन्द। (तालियां)

श्री उपाध्यक्षः अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक ऐडजर्न किया जाता है।

11. 51 बजे।

(तत्पश्चात सदन वीरवार दिनांक 9 मार्च, 1989 को प्रातः 9.30 बजे तक स्थगित हुआ)